● वर्ष-2
● अंक-280
रायपुर, शनिवार
15 जुलाई 2023
● पृष्ठ-6
● मूल्य-3 रु.
samacharpacheesa@gmail.com

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

इन दिनों ✍ शशांक शर्मा

भ्रष्टाचार पर आमने सामने की राजनीति

छत्तीसगढ़ में चुनाव निकट है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी एक दूसरे पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। केंद्र में स्थिति अलग है, भाजपा आज भी कांग्रेस के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के कार्यकाल में हुए भ्रष्टाचार को 9 साल बाद भी मुद्दा बनाए हुए हैं। शुक्रवार को एनडीए सरकार के कार्यकाल में हुए कोयला घोटाले के आरोपी कांग्रेस पार्टी के सांसद और उनके पुत्र को कोर्ट ने दोषी ठहराया है। लेकिन विपक्ष के पास अभी केंद्र सरकार के खिलाफ कोई भ्रष्टाचार का मुद्दा नहीं है। छत्तीसगढ़ में विचित्र स्थिति है, कांग्रेस पार्टी की सरकार है और डॉ. रमन सिंह सरकार पर अभी भी कांग्रेस के नेता भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है। यह समझ से परे है कि सरकार की ताकत कांग्रेस के पास है। प्रशासनिक अमला है, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्यवाही करने वाली व्यवस्था है, कोर्ट है, सब कुछ है लेकिन सरकार कारवाई नहीं कर पा रही है। ऐसी बात नहीं है कि भूपेश सरकार कुछ करना नहीं चाहती, 2018 दिसंबर में सरकार बनने के बाद एक के बाद एक जांच टीम एसआईटी का गठन किया है। लेकिन पौने पांच साल के बाद भी एसआईटी की टीम किसी आरोप को साबित नहीं कर पाई है। दूसरी ओर प्रदेश सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं, कोयला में परिवहन परमिट के नाम पर अवैध वसूली का घोटाला 500 करोड़ से ऊपर का है। शराब घोटाला तो अपने आप में अनोखा है। कोई सरकार पर अपने खजाने में आने वाले राजस्व की चोरी करने जा आरोप तो निराला ही है। ये आरोप कोई हवा में नहीं हैं बल्कि प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने बकायदा जांच करके कोर्ट में जो चलन प्रतीत किया है उसमें पूरा विवरण दिया है। जब भी इस प्रकार के भ्रष्टाचार का उल्लेख भाजपा करती है तो कांग्रेस पार्टी के नेता भाजपा सरकार के समय भ्रष्टाचार की दुहाई देने लगते हैं मानो पिछली सरकार पर आरोप लगाने से वर्तमान सरकार को घोटाले करने का परमिट मिल जाता है। अपने घोषणा पत्र में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने कांग्रेस पार्टी ने मजबूत लोक आयोग बनाने का संकल्प लिया था जिसकी सीमा में मुख्यमंत्री भी आते हैं लेकिन सरकार बनने के बाद भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना तो दूर जो आरोप खुद कांग्रेस लगाती थी, उन पर कार्यवाही करने में सरकार अक्षम है। लगता है छत्तीसगढ़ की राजनीति में भ्रष्टाचार का मुद्दा केवल आरोप प्रत्यारोप तक सीमित रहेगा। इन्हीं कारणों से जनता के मन में राजनेताओं के बारे में धारणा बनती जा रही है कि सभी भ्रष्ट होते हैं। ऐसा विचार फिर समाज में भ्रष्टाचार को मान्यता दे देता है जैसे कि प्रशासन में अधिकायों और कर्मचारियों को मान्यता मिली हुई है। नेता भी अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं लड़ेगा तो इस नासूर का ईलाज कौन करेगा?

फ्रांस में भारत का डंका, मोदी के दीवाने हुए

भारतीय सैन्य दल ने सारे जहां से अच्छा की धुन पर मार्च किया

नईदिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिवसीय फ्रांस की यात्रा पर है। यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत किया गया है। फ्रांस की धरती से लेकर आसमान तक हिंद की धूम नजर आई। जहां एक तरफ भारतीय सैन्य दल ने सारे जहां से अच्छा की धुन पर मार्च किया, जबकि भारतीय वायु सेना (आईएएफ) के राफेल लड़ाकू विमानों ने बैस्टिल डे परेड में चैंप्स-एलिसीज़ के ऊपर फ्लाईपास्ट में भाग लिया। पंजाब रेजिमेंट ने मार्च का नेतृत्व किया और उसके बाद भारतीय नौसेना और फिर वायु सेना ने 1789 में बैस्टिल के ऐतिहासिक पतन को चिह्नित करने के लिए वार्षिक परेड में अपनी छाप छोड़ी। पंजाब रेजिमेंट का नेतृत्व कैप्टन अमन जगताप ने किया, जो भारतीय नौसेना के थे। दल का नेतृत्व कमांडर व्रत बघेल ने किया। भारतीय वायु सेना दल की कमान स्क्वाड्रन लीडर सिंधु रेड्डी ने संभाली।

1789 में बैस्टिल के ऐतिहासिक पतन की याद में वार्षिक परेड में पंजाब रेजिमेंट ने मार्च शुरू किया, जिसके बाद भारतीय नौसेना और भारतीय वायु सेना (आईएएफ) ने मार्च किया। कैप्टन अमन जगताप पंजाब रेजिमेंट के प्रभारी थे, जबकि कमांडर व्रत बघेल भारतीय नौसैनिक उपस्थिति के प्रभारी थे। स्क्वाड्रन लीडर सिंधु रेड्डी भारतीय वायु सेना टीम के प्रभारी थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में सम्मानित अतिथि के रूप में मौजूद रहे। उन्होंने चैंप्स-

एलिसीज़ में मार्च करते हुए भारतीय दल की सलामी ली।

मोदी ने किया फुटबॉलर का जिक्र

फ्रांस की प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बोर्न ने हवाई अड्डे पर पहुंच कर पीएम मोदी की अगवानी की है। इसके बाद पीएम मोदी ने अपना संबोधन भी दिया है, जिसमें उन्होंने फुटबॉलर किलियन एम्बाप्पे का खास जिक्र किया है। पीएम मोदी द्वारा किलियन एम्बाप्पे का जिक्र करना सुर्खियां बटोर रहा है। गौरतलब है कि किलियन एम्बाप्पे दुनिया के शानदार फुटबॉलर में शुमार है। दुनिया के बेहतरीन फुटबॉलरों में उनका नाम शामिल किया जाता है। फीफा विश्व कप जीतने वाली टीम का हिस्सा भी एम्बाप्पे रह चुके है। उनकी टीम ने 2018 में विश्व कप जीता था। ऐसे में इस शानदार खिलाड़ी का जिक्र पीएम मोदी ने भी फ्रांस यात्रा के दौरान किया है।

बता दें कि इस यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने पेरिस में ला सीन म्यूजिकल में भारतीय समुदाय को संबोधित भी किया है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के फुटबॉलर और फ्रांस की टीम के कप्तान किलियन एम्बाप्पे का भी जिक्र किया है। किलियन एम्बाप्पे का नाम सुनकर भारतीय समुदाय के लोग भी उत्सुक हो गए और चीयर करने लगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि फ्रांस के फुटबॉलर की प्रसिद्धि भारत आकर देखनी चाहिए। एम्बाप्पे के जितने फैंस फ्रांस में नहीं होंगे उससे अधिक भारत में है। एम्बाप्पे भारत के युवाओं के बीच बेहद लोकप्रीय है।

गौरतलब है कि किलियन एम्बाप्पे बेहद लोकप्रिय फुटबॉलर है, जिन्होंने फ्रेंच लीग और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने दमदार खेल की बदौलत शानदार उपलब्धि हासिल की है। विश्व के चुनिंदा लोकप्रिय खिलाड़ियों में उनका नाम शुमार है। विश्व कप 2022 में अर्जेंटीना के खिलाफ फाइनल मुकाबले में किलियन एम्बाप्पे ने हैट्रिक मारी थी, जिसके बाद वो अधिक लोकप्रिय हो गए थे। इस मुकाबले में हारने के बाद मैदान पर पहुंचकर खुद राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रां ने किलियन एम्बाप्पे का हौंसला बढ़ाया था जिसकी फोटोज और वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई थी।

मोदी फ्रांस के सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित

नईदिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ्रांस ने लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है, जो कि सर्वोच्च फ्रांसीसी सम्मान है। ये पुरस्कार पाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री है। उनसे पहले ये पुरस्कार कुछ चुनिंदा नेताओं और प्रतिष्ठित हस्तियों को सौंपा गया है। प्रधानमंत्री इसके अवाला बैस्टिल परेड का भी हिस्सा है, जिसमें भारत की भी तीनों सेनाएं शामिल है।

बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा ये पुरस्कार पहले दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला, वेल्स के तत्कालीन राजकुमार किंग चार्ल्स, जर्मनी की पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल, संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव बुट्रोस बुट्रोस-घाली को मिल चुका है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई देशों की यात्रा के दौरान कई बार सम्मानित हो चुके है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार और सम्मानों से सम्मानित किया गया है। उन्हें कई देशों का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिल चुका है। इस सूची में अब फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान भी शामिल हो गया है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले ये सम्मान उनके नेतृत्व और दूरदृष्टि का प्रतिबिंब है। उन्होंने जिस तरह से भारत को वैश्विक मंच पर मजबूती प्रदान की है ये उसका ही नतीजा है। इन पुरस्कारों से ये भी साबित होता है कि दुनिया भर के देशों के साथ भारत के संबंध बेहद मजबूत हो रहे है। बता दें कि इससे पहले पीएम मोदी को जून के महीने में मिस्त्र की यात्रा के दौरान ऑर्डर ऑफ द नाइल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इससे पहले मई 2023 में वो पापुआ न्यू गिनी की यात्रा पर थे जहां उन्हें कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू से सम्मानित किया गया था।

सीएम से मरकाम ने की सौजन्य मुलाकात

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से आज यहाँ उनके निवास में नवनियुक्त मंत्री मोहन मरकाम ने सौजन्य मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने श्री मरकाम को नई जिम्मेदारी मिलने पर बधाई और शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत, कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, वन मंत्रीी मोहम्मद अकबर, नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया, नवनियुक्त मंत्री श्री मरकाम की धर्मपत्नी और बच्चे भी उपस्थित थे।

कोयला ब्लॉक आवंटन में कांग्रेस के पूर्व सांसद व उनके बेटे दोषी करार

नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने छत्तीसगढ़ में कोयला ब्लॉक आवंटन में अनियमितता से संबंधित एक मामले में राज्यसभा के पूर्व सांसद विजय दर्डा, उनके बेटे देवेन्द्र दर्डा, पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता और चार अन्य को दोषी ठहराया है। विशेष न्यायाधीश संजय बंसल ने गुरुवार को सातों को

भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 120बी (आपराधिक साजिश) और 420 (धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति की डिलीवरी के लिए प्रेरित करना) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दोषी ठहराया। एलडी यवतमाल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक मनोज कुमार जयसवाल और दो अधिकारी के एस क्रोफा और के सी सामरिया उन अन्य लोगों में शामिल हैं जिन्हें दोषी ठहराया गया है। इस मामले में सजा पर बहस के लिए मामले को 18 जुलाई को सूचीबद्ध किया गया है।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (ष्टक्चढ्ढ) ने कहा कि कोयला आवंटन घोटाले में 13वीं सजा सुनिश्चित की गई है। आपको बता दें कि 2012 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार को कोयला घोटाले ने हिलाकर रख दिया था।

2014 में सुप्रीम कोर्ट ने 1993 से बिजली, स्टील और सीमेंट कंपनियों को 200 से अधिक कोयला ब्लॉकों के आवंटन को अवैध घोषित कर दिया। 2012 में अपनी रिपोर्ट में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने कहा कि कम कीमत पर बिक्री से सरकारी खजाने को नुकसान होता है। इस घोटाले को कोलगेट करार दिया गया था।

छत्तीसगढ़ में कोयला ब्लॉक आवंटन से संबंधित मामले में अपनी पहली एफआईआर में सीबीआई ने कहा कि जेएलडी यवतमाल ने 1999-2005 में अपने समूह की कंपनियों को चार कोयला ब्लॉकों के पिछले आवंटन को गलत तरीके से.. छुपाया। बाद में एक क्लोजर रिपोर्ट दायर की गई जिसमें कहा गया कि कोयला मंत्रालय ने कंपनी को कोई अनुचित लाभ नहीं दिया।

रिपोर्ट में कहा गया है कि यह साबित करने के लिए कुछ भी ठोस सामने नहीं आया कि कोयला मंत्रालय के अधिकारी और एलडी यवतमाल एनर्जी के निदेशक धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश में शामिल थे। ट्रायल कोर्ट ने नवंबर 2014 में क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और सीबीआई को मामले में आगे की जांच करने का निर्देश दिया। इसमें कहा गया है कि विजय दर्डा ने मनमोहन सिंह को लिखे पत्रों में तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया, जिनके पास उस समय कोयला विभाग था ।

प्रमुख समाचार

राज्य योजना आयोग के अध्यक्ष बने प्रेमसाय सिंह टेकाम

रायपुर। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में इन दिनों बदलाव और फेरबदल का दौर चल रहा है। आज पूर्व पीसीसी चीफ मोहन मरकाम के कैबिनेट मंत्री पद की शपथ लेने के बाद पूर्व मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम

को राज्य योजना आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। इसके साथ ही उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी दिया गया है। मरकाम के शपथ ग्रहण के बाद आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सीएम हाउस में आज मंत्रियों की एक अहम बैठक ली। इसमें मंत्री रूद्रकुमार गुरु, शिव डहरिया, कवासी लखमा, रविन्द्र चौबे, ताम्रध्वज साहू, मोहम्मद अकबर आदि मौजूद रहे। इसमें विभागों के फेरबदल को लेकर चर्चा की गई है। सूत्रों के अनुसार, मंत्री रविन्द्र चौबे के स्वास्थ्य को देखते हुए उनके विभाग को कम किया जा सकता है। वहीं ताम्रध्वज साहू को कृषि विभाग की अहम जिम्मेदारी मिल सकती है। वहीं मोहन मरकाम को स्कूल शिक्षा विभाग, सहकारिता विभाग का जिम्मा मिल सकता है। वहीं संभव है कि डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव को भी कोई नया विभाग मिल सकता है। नए विभागों को लेकर देर शाम तक नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है।

शिंदे गुट की बढ़ी मुश्किलें! सुको ने जारी किया नोटिस

नईदिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके समर्थक विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय लेने में देरी की शिकायत करने वाली याचिका पर महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को नोटिस जारी किया। अविभाजित शिव सेना के मुख्य सचेतक के तौर पर शिव सेना (यूबीटी) के विधायक सुनील प्रभु प्रभु ने पिछले साल शिंदे और अन्य 15 विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिका दायर की थी, क्योंकि उन्होंने जून 2022 में बगावत कर नई सरकार बनाने के लिए भाजपा से हाथ मिला लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर दो हफ्ते में जवाब मांगा है। प्रभु ने इस महीने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया और अयोग्यता याचिकाओं पर शीघ्रता से सुनवाई करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष को निर्देश देने की मांग की, उन्होंने दावा किया कि नार्वेकर जानबूझकर सुनवाई में देरी कर रहे थे, जबकि उच्चतम न्यायालय ने 11 मई के अपने फैसले में विधानसभा अध्यक्ष से याचिकाओं पर समय सीमा के भीतर उचित तरीके से निर्णय लेने के लिए कहा था। पीठ ने कहा, हम दो सप्ताह में वापस करने योग्य नोटिस जारी करेंगे। इस पीठ में न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल हैं।

बीबीसी डॉक्यूमेंट्री मामले में हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती

दिल्ली । दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को पीएचडी विद्वान लोकेश चुघ से उस आदेश के खिलाफ दिल्ली विश्वविद्यालय की याचिका पर जवाब मांगा, जिसमें बीबीसी डॉक्यूमेंट्री इंडिया- द

को प्रदर्शित करने के प्रयास में कानून और व्यवस्था की गड़बड़ी में कथित संलिप्तता के लिए उन्हें एक साल के लिए प्रतिबंधित करने वाले ज्ञापन को रद्द कर दिया गया था। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति नजमी वजीरी की खंडपीठ ने एनएसयूआई के राष्ट्रीय सचिव चुघ को नोटिस जारी किया और मामले को 14 सितंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। 27 अप्रैल को न्यायमूर्ति पुरुषइंद्र कुमार कौरव की एकल-न्यायाधीश पीठ ने यह कहते हुए ज्ञापन को रद्द कर दिया था कि वर्तमान मामले के तथ्यों, विशेष रूप से लागू आदेश के अवलोकन से अदालत ने पाया कि इसे बिना उचित निर्णय के पारित किया गया है। याचिकाकर्ता को सुनने या उसके स्पष्टीकरण पर विचार करने का अवसर, जैसा कि उदिनांक 20.02.2023 को अपनी प्रतिक्रिया के संदर्भ में प्रस्तुत किया था।

ठीक नहीं है सेना पर कीचड़ उछालना: अमेरिकी राजदूत

नईदिल्ली। दो महीने से ज्यादा वक्त हो गया, मणिपुर में सुधरते-बिगड़ते हालात के बीच आ रहे बयानों से हमारे माथे पर चिंता की लकीरें पड़नी चाहिए। अमेरिका में प्यार की पींगों के बाद अमेरिकी राजदूत एरिक गार्सेटी ने कोलकाता स्थित अमेरिकी वाणिज्य दूतावास में संवाददाताओं से बात करते हुए कहा कि मणिपुर की घटनाएं मानवीय चिंता का विषय हैं। अंग्रेजी दैनिक द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने कहा, हम शांति की कामना करते हैं। जब आप हिंसा में बच्चों को मरता देख रहे हों, तब आपको परवाह करने के लिए भारतीय होना जरूरी नहीं है। अगर कहा जाए, तो हम हर तरह से सहायता करने को तैयार हैं। मार्गदर्शक सिद्धांत यह हो कि हर व्यक्ति जुड़ाव महसूस करे। हम वहां अधिक सहकार, अधिक परियोजनाएं और अधिक निवेश ला सकते हैं। भारत के पूर्व और पूर्वोत्तर से हमारा सरोकार है। यहां के लोगों, स्थानों, क्षमताओं और भविष्य से हमारा सरोकार है। म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान से लगे चीन की पहुंच वाले क्षेत्र में बेलौस मुहब्बत तो यह फिक्र नहीं पैदा कर रही, हालांकि गार्सेटी ने यह बताना आवश्यक समझा कि अमेरिका का सरोकार सामरिक नहीं है।

ज्ञानवापी मस्जिद में कोर्ट ने सुरक्षित रखा अपना आदेश

नईदिल्ली। वाराणसी की एक जिला अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वेक्षण के तहत कार्बन डेटिंग पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट 21 जुलाई को अपना फैसला सुनाएगी। इस साल मई में अदालत काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में स्थित पूरे ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा सर्वेक्षण के लिए एक याचिका पर सुनवाई करने के लिए सहमत हुई थी। कोर्ट ने हिंदू पक्ष

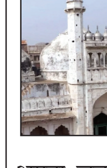

का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील विष्णु शंकर जैन की याचिका स्वीकार कर ली थी। विष्णु जैन की याचिका पर विचार करने के बाद, अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद समिति को हिंदू पक्ष द्वारा दी गई दलीलों पर अपना जवाब दाखिल करने को कहा। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अब कार्बन डेटिंग पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। कुछ दिन पहले, हिंदू याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट से इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई का आग्रह किया था, जिसमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर के परिसर में शिवलिंग की वैज्ञानिक जांच करने का निर्देश दिया गया था।

चंद्रयान-3 का सफल प्रक्षेपण, मिशन की सफलता से देश पर बरसेंगे डॉलर

चंद्रयान-2 की लॉन्चिंग के 3 साल 11 महीने और 23 दिन बाद आखिर वो घड़ी आ ही गई जब एक बार फिर चंद्रयान-3 मिशन के साथ चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। 14 जुलाई को दोपहर 2.30 बजे श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। 50 वर्ष पहले की तुलना में यह कार्य अभी भी काफी कठिन है। एक बार फिर भारत की ये कोशिश की अपना डंका पूरे अंतरिक्ष में बजाया जाए। एक के बाद एक तमाम लेवल को क्रास करता हुआ चंद्रयान-3 चांद के सफर पर निकल चुका है।

अभी तक कोई देश यहां नहीं पहुंचा है। चंद्रयान-1 मिशन के दौरान साउथ पोल में बर्फ के बारे में पता चला था। यहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती। चांद के साउथ पोल में ठंडे क्रेटर्स (गड्ढों में शुरुआती सौर प्रणाली के लुप्त जीवाश्म रिकॉर्ड मौजूद हो सकते हैं। अगर चंद्रयान-3 यहां लैंड करता है तो यह पहली बार होगा।

चंद्रयान 3 की सफलता, दुनिया में भारत के लिए तरक्की की नई राहें प्रशस्त करेगी। यूं समझ लें, यह एक इतिहास रचा जाएगा। इसकी सफलता से एक-दो नहीं, बल्कि अनेकों क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिलेंगे। बॉर्डर पर चीन जैसे शत्रु राष्ट्र, जो आए दिन कोई न कोई खुराफात करते रहते हैं, उन पर नजर रखना आसान हो जाएगा। दुश्मन की सेना की मिनट-टू-मिनट मूवमेंट का पता चलेगा। हैवी मिसाइल दागने के लिए एक विश्वसनीय प्लेटफार्म उपलब्ध होगा। जब भारत में पे लोड की क्षमता बढ़ेगी, तो दुनिया के कई देश अपने उपग्रहों की लॉंचिंग के लिए भारत से संपर्क करेंगे। चंद्रयान 3 की सफलता से भारत पर डॉलर बरसने लगेंगे। कई बार ऐसी खबरें हमें विचलित करती हैं कि फलां उल्का पिंड, पृथ्वी से टकरा जाएगा। ऐसे में लोगों की सांस थमने लगती हैं। अभी इस तरह की गतिविधियों पर पृथ्वी से नजर रखना आसान नहीं है। लिहाजा चंद्रमा का वातावरण पूरी तरह साफ रहता है तो वहां से कोई भी वस्तु स्पष्ट नजर आती है।

इसके अलावा चंद्रयान-3 की कामयाबी भारत को पृथ्वी से बाहर यानी चंद्रमा पर एक स्टेशन तैयार करने का अवसर प्रदान करेगी। यहां से दूसरे ग्रहों पर जाना आसान हो जाएगा।

दुनिया में आज स्पेस डोमेन का संघर्ष है

पूर्व वैज्ञानिक एवं प्रमुख रेडियो कार्बन डेटिंग लैब, बीरबल साहनी पुराविज्ञान संस्थान, लखनऊ, डॉ. सीएम नौटियाल ने अमर उजाला डॉट कॉम के साथ बातचीत में यह बात कही है। भारत से लगती चीन सीमा पर कुछ वर्षों से घुसपैठ की गतिविधियां बढ़ रही हैं। चीन की सेना के भारतीय क्षेत्र में आने की खबरें आती रहती हैं। हालांकि भारत की ओर से उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाता है। चीन से लगती सीमा पर भी बड़ी संख्या में ऐसे ड्रोन की उपस्थिति बताई गई है, जिन्हें बिना किसी दूरबीन के देखना संभव नहीं होता। दुश्मन के ड्रोन का मुकाबला करने बाबत इंडियन स्पेस एसोसिएशन के डीजी ले. जनरल (रि) एके भट्ट कहते हैं, आज स्पेस डोमेन का संघर्ष है। परंपरागत लड़ाई के तरीकों की जगह आज 3डी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 5जी और क्वांटम तकनीक ने ले ली है।

72 सैटेलाइट से बॉर्डर पर सर्विलांस कर रहा चीन

सुरक्षा के मोर्चे पर ये बड़ी चुनौती है। सैन्यकरण के अंतर्गत जल, थल और वायु में पीस/वॉर टाइम के दौरान तकनीक का इस्तेमाल करना होगा। इसके जरिए हमें खुद के उपकरणों को बचाते हुए दूसरे का मुकाबला करना है। निजी सैटेलाइट का जमाना आ चुका है। एलन मस्क इसका एक उदाहरण हैं। मौजूदा समय में 92 देशों ने स्पेस में अपने सैटेलाइट उतार दिए हैं। खाड़ी देशों ने भी पैसे के बल पर यह स्थिति हासिल कर ली है। इसरो आत्मनिर्भरता की राह पर है। मिलिट्री पॉजिशन, स्नूपिंग या आतंकियों की मदद में ड्रोन का प्रयोग होता है। चीन अपने मिलिट्री ड्रोन के जरिए जल, थल और वायु सटीक सर्विलांस करता है। इसके लिए उसने 72 सैटेलाइट तैयार किए हैं। युद्ध पोतों पर उसकी नियमित नजर रहती है।

कई द्वार खोलेगी चंद्रयान 3 की सफलता

डॉ. सीएम नौटियाल के मुताबिक, चंद्रयान 3 की सफलता हमारे लिए कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है। इससे चंद्रमा पर भारत की सुरक्षित लैंडिंग की क्षमता का प्रदर्शन होगा। साल 2019 में चंद्रयान 2 मिशन के अंतर्गत लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग में सफलता नहीं मिल सकी थी। इस बार चंद्रयान 3 को लेकर हर तरह की प्रतिकूल संभावनाओं के बारे में पहले से सोचा गया है। अंतिम रणनीति तय हो चुकी है। इस तरह की सफलता से स्पिन ऑफ यानी कई तरह की दूसरी तकनीक विकसित होती हैं। उद्योगों में उन वस्तुओं और तकनीक का भरपूर इस्तेमाल होता है। नए पदार्थ, यूनिट और सॉफ्टवेयर आदि विकसित होते हैं। नासा ने भी इस तरह की सफल लॉंचिंग के बाद विभिन्न उपकरणों और तकनीक का उपयोग उद्योगों में किया जा रहा है। एक असफलता के चार साल बाद चंद्रयान-3 भेजने का साहस करना, ये बहुत बड़ी बात है। इसकी सफलता पर हर कोई गर्व करेगा। लॉंचिंग क्षमता, पे लोड उपलब्धि और सुरक्षा के मोर्चे पर, भारत की ताकत बढ़ जाएगी। भारत की मिसाइल तकनीक में एक बड़ी मदद मिलेगी। उपग्रह भेजने के लिए भारत क्षमता बढ़ जाएगी। मौसम की सटीक भविष्यवाणी करना आसान होगा। भारी उपग्रह भेजने की क्षमता में अपेक्षित सुधार आएगा। इसके अलावा अंतरिक्ष की मैंपिंग के क्षेत्र में भी बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे।

इनामी नक्सली लीडर मड़कम देवा ने किया आत्मसमर्पण

रायपुर। छत्तीसगढ़ में 190 जवानों की हत्या करने वाला इनामी नक्सली लीडर मड़कम देवा ने सरेंडर कर दिया है। मड़कम देवा उर्फ भगत ने एपी पुलिस के सामने सरेंडर किया है। मड़कम देवा पर 5 लाख रुपये का इनाम घोषित था। सरेंडर के बाद नक्सली लीडर को 5 लाख रुपये की इनाम राशि दी जाएगी। मड़कम देवा उर्फ भगत 17 साल से ज्यादा समय से अलग अलग नक्सली घटनाओं में शामिल रहा है। इंजरम गांव के माओवादियों द्वारा सल्वाजुडेम शिविर पर हमले सहित 12 से अधिक गंभीर अपराधों में आरोपी है। पुलिस अधिकारी के अनुसार, उसने एएसआर जिला अधीक्षक तुहिन सिन्हा के सामने आत्मसमर्पण कर दिया।

साल 2005 में नक्सल संगठन से जुड़ा देवा

साल 2005 में देवा कोंटा और दोरनापाल क्षेत्र समितियों के प्रभारी नक्सली नेता विजय के साथ गनमैन के रूप में तैनात किया गया था और 2007 तक काम किया। साल 2008 में, देवा को 8वीं कंपनी में स्थानांतरित कर दिया गया। जहां उसने एक अन्य माओवादी नेता सिंगन्ना की कमान में एक साल तक काम किया, जिसने 2012 में आत्मसमर्पण कर दिया था।

सुकमा की नक्सली सदस्य से की शादी

2009 में, देवा ने अपनी टीम के सदस्यों में से एक, मादिवी मल्ले उर्फ गंगी से शादी की, जो छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के किस्टाराम पुलिस स्टेशन क्षेत्र के तहत मेट्टागुडेम गांव की मूल निवासी थी। इसी साल अगस्त सितंबर में पहली बटालियन का गठन किया गया और देवा को पहली कंपनी की दूसरी प्लाटून में सेक्शन कमांडर के रूप में तैनात किया गया। मार्च 2010 में बटालियन कमांडर मादिवी हिदुमा ने देवा को पीपीसीएम के रूप में पदोन्नत किया और उसे बटालियन के आपूर्ति टीम कमांडर के रूप में तैनात किया। सितंबर 2013 में, देवा को कंपनी पार्टी समिति के सदस्य के रूप में पदोन्नत किया गया था।

इन बड़ी घटनाओं में शामिल था सरेंडर नक्सली

देवा 2004 में कोंटा सहित माओवादियों द्वारा किए गए आईईडी विस्फोट में शामिल था, जिसमें लॉरी में यात्रा कर रहे 12 पुलिसकर्मी मारे गए थे। साल 2006 में, इंजरम गांव के माओवादियों द्वारा सल्वाजुडेम कैंप पर हमले में शामिल था, जिसमें दो सुरक्षा बल के जवान और 4 ग्रामीण मारे गए थेसाल 2006 में ही बड़े नक्सली हमले में शामिल था जिसमें 7 सीआरपीएफ कमांडो मारे गए थे।

वर्ष 2008 में सुकमा जिले के चिंतागुप्पा गांव के पास मिनपा गांव में तीसरी कंपनी और 8वीं कंपनी सहित माओवादियों द्वारा लगाए गए हमले में शामिल था, जिसमें 12 सीआरपीएफ जवान मारे गए थे।वर्ष 2009 में सुकमा जिले के चिंतागुप्पा गांव के पास, सिंगन्ना मडुगु गांव में पहली बटालियन सहित माओवादियों द्वारा लगाए गए हमले में शामिल थे, जिसमें 6 कोबरा कमांडो मारे गए थे। वर्ष 2010 में सुकमा जिले के चिंतागुप्पा थाने के पास पहली बटालियन और दूसरी सीआरसी जरमेटा गांव में माओवादियों द्वारा लगाए गए हमले में शामिल था, जिसमें 76 सीआरपीएफ कमांडो मारे गए थे।

2014 में सुकमा जिले के चिंतागुप्पा थाने के पास कसालपाडु गांव में पहली बटालियन सहित माओवादियों द्वारा लगाए गए हमले में भी शामिल था, जिसमें 14 सीआरपीएफ कमांडो मारे गए थे।

नक्सली विचारधारा से परेशान होकर किया सरेंडर

पुलिस ने बताया कि सरेंडर नक्सली मड़कम देवा नक्सल सिद्धांतों से परेशान और गैर-आदिवासी सदस्यों के खिलाफ भेदभाव से निराश था। इसी वजह से उसने सरेंडर करने का फैसला किया।

मंदिर में तोड़फोड़, शिवलिंग समेत कई मूर्तियां तोड़ी

कोरबा। छत्तीसगढ़ के कोरबा में गुरुवार देर रात कुछ लोगों ने शिव मंदिर में तोड़फोड़ कर दी। मंदिर का ताला तोड़कर घुसे बदमाशों ने अंदर स्थापित शिवलिंग सहित कई मूर्तियों को खंडित कर दिया। इसके साथ ही वहां रखा सारा सामान भी चोरी कर ले गए। घटना का पता लोगों को शुक्रवार सुबह चला। इसके बाद हंगामा मच गया है। सावन माह में शिव मंदिर में हुई तोड़फोड़ ने लोगों को आक्रोशित कर दिया है। खास बात यह है कि मंदिर रेलवे स्टेशन के सामने है। इसके बाद भी वारदात का पता नहीं चला। जानकारी के मुताबिक, कोतवाली क्षेत्र में रेलवे स्टेशन के सामने वर्षों पुरान शिव मंदिर है। यहां पर रेलवे कॉलोनी सहित आसपास के लोग रोज पूजा-अर्चना करने के लिए जाते हैं। शुक्रवार सुबह भी जब लोग पूजा करने के लिए पहुंचे तो देखा कि मंदिर के गेट पर लगा ताला टूटा हुआ था। इस पर वे अंदर गए तो शिवलिंग सहित वहां लगी नंदी की प्रतिमा और अन्य देवी-देवताओं की प्रतिमा में तोड़फोड़ की गई थी। वहां रखा सारा सामान त्रिशूल, भगवान के गहने सब गायब थे।

सीआरपीएफ की जमीन विवाद का नहीं निकला हल, बीएसपी ने सीमांकन करने से किया इनकार

भिलाई। सीआरपीएफ और भिलाई इस्पात संयंत्र के बीच जमीन का मामला नहीं सुलझ सका है। सीआरपीएफ ने 250 एकड़ जमीन बीएसपी से साल 1971 में ली थी।इसके लिए बकायदा सीआरपीएफ ने बीएसपी प्रबंधन को रकम भी अदा की थी। लेकिन सीआरपीएफ की जमीन पर अवैध तरीके से नेहरु नगर समेत कई कॉलोनियां बस गईं। इस मामले में तत्कालीन विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण यानी साडा और बीएसपी प्रबंधन की लापरवाही सामने आई है। जिसके कारण सीआरपीएफ को उनकी जमीन पर अब तक कब्जा नहीं मिल पाया है।

इस मामले को लेकर गुरुवार शाम निगम कार्यालय भिलाई में एक महत्वपूर्ण त्रिपक्षीय बैठक हुई। सीआरपीएफ के अफसरों के मुताबिक पंजीयक और निगम का कहना है कि सीआरपीएफ ने जमीन बीएसपी से खरीदी थी।इसलिए पूरी 250 एकड़ जमीन का सीमांकन बीएसपी मैनेजमेंट करवा करे। लेकिन बैठक में निगम और सीआरपीएफ के कहने के बाद भी बीएसपी के अफसर सीमांकन करने के लिए राजी नहीं हुए। जिसके कारण बैठक बेनतीजा रही।

सीआरपीएफ के डीआईजी बलराम बेहरा ने कहा कि बीएसपी से 250 एकड़ जमीन 2 लाख 19 हजार 236 रूपए 53 पैसे में ली गई। इस पूरी राशि का भुगतान 23 फरवरी 1971 को किया गया। इसके बाद बीएसपी ने 18 अप्रैल 1972 को सीआरपीएफ को 232.02 एकड़ जमीन सौंपी। लेकिन इस जमीन पर अवैध कॉलोनी विकसित हो गई। इसमें तत्कालीन मध्यप्रदेश शासन से 24 अप्रैल 1991 को एक अप्रुवल की बात साडा की ओर से कई गई थी। लेकिन साडा का दावा गलत है क्योंकि अवैध कॉलोनियां साडा और बीएसपी प्रबंधन के कारण हीं बसी है।

सीआरपीएफ ने बीएसपी से पूछे सवाल

सीआरपीएफ ने बीएसपी प्रबंधन से सवाल पूछे थे। जिसमें ये कहा गया है कि बीएसपी प्रबंधन ने जो राशि सीआरपीएफ से ली वो किस खाते में गई।इसके बाद सीआरपीएफ की जमीन को अवैध तरीके से बेचकर करोड़ों का लाभ किसने कमाया है।लेकिन इन सवालों का जवाब भी ना तो साडा के पास था और ना ही बीएसपी प्रबंधन के पास इस मुद्दे पर दोनों पक्षों में जमकर बहस हुई जिसके बाद बीएसपी के अफसर बैठक छोड़कर निकल गए।आपको बता दें कि नगर निगम भिलाई ने भी सीआरपीएफ की जमीन पर पानी की टंकी बना दी है। इसी जगह पर अभी सीआरपीएफ की एक टुकड़ी 5 अक्टूबर 18 से काबिज है।

इस बैठक में सीआरपीएफ की ओर से डीआईजी बलराम बेहरा, कमांडेंट अनुपम श्रीवास्तव, इंस्पेक्टर ग्लैडविन जॉन, एएसआई (मंत्रालय) काजल हजारी, नगर निगम भिलाई की ओर से अशोक द्विवेदी अतिरिक्त कमिश्नर, रमाकांत साहू उप कमिश्नर और प्रीति सिंह राजस्व और भिलाई स्टील प्लांट की ओर से सुब्रत प्रहराज जनरल मैनेजर, शुरोजित मल्लिक उपमहाप्रबंधक और अनुपम शिवप्पा सहायक महाप्रबंधक उपस्थित थे।

सहकारी बैंक में 106 करोड़ का घोटाला मामला

हाईकोर्ट ने मांगी जांच एजेंसियों से रिपोर्ट

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने जिला सहकारी बैंक में हुए 106 करोड़ रुपए के घोटाले पर संज्ञान लिया है।हाईकोर्ट ने नोटिस जारी करके मुख्य सचिव, सचिव सामान्य प्रशासन, ईओडब्ल्यू के एडीजीपी से मामले में जवाब मांगा है। इन सभी से जांच करने के बाद कोर्ट में चालान पेश नहीं करने को लेकर व्यक्तिगत रूप से शपथ पत्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए है। कोर्ट ने इस मामले में चालान पेश करने में समय लगने का कारण पूछा है। इस मामले की अगली सुनवाई 25 जुलाई को होगी।

जांच को लेकर लगाई गई थी याचिका- बिलासपुर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में 2011 में तत्कालीन अध्यक्ष और तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने कथित भ्रष्टाचार किया था।जिसे लेकर कोर्ट में याचिका लगाई गई थी। याचिका में बताया गया है कि बिलासपुर के जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में 106 करोड़ रुपए के घोटाले में संलिप्त लोगों के खिलाफ ईओडब्ल्यू और एंटी करप्शन ब्यूरो जांच कर रही थी, लेकिन जांच पूरी नहीं हुई। मामले में कोर्ट में चालान भी पेश भी नहीं किया गया।

क्या है मामला- 26 अगस्त 2011 को जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष देवेंद्र पाण्डेय और सीएमओ बीएस बिसेन के खिलाफ शिकायत हुई थी।जिसमें 106 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप था।जिसकी जांच ईओडब्लू ने की। 27 अगस्त 2011 को थाना ईओडब्लू और एसीबी रायपुर ने एफआईआर दर्ज की थी। 11 साल के बाद भी 23 फरवरी 2022 को अध्यक्ष देवेंद्र पांडेय और सीईओ वीएस बिसेन के खिलाफ धारा 409 और 120 बी भारतीय दंड विधान धारा 7(सी) 13(1)(ए), 13 (2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 संशोधित अधिनियम 2018 के तहत एफआईआर दर्ज किया गया था। इसके बाद इतना समय बीतने पर भी अब तक विवेचना पूरी कर चालान कोर्ट में पेश नहीं किया गया है।

अघोषित बिजली कटौती के विरोध में जनकपुर-मनेंद्रगढ़ मार्ग पर चक्काजाम

अघोषित बिजली कटौती का ग्रामीणों ने किया विरोध

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। छत्तीसगढ़ के मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले में अघोषित बिजली कटौती को लेकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। मनेंद्रगढ़ में लोग शुक्रवार को सड़क पर उतर आए और जनकपुर-मनेन्द्रगढ़ मुख्य मार्ग पर चक्का जाम कर दिया है। लोग सड़क पर लालटेन लेकर बैठे हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि भरतपुर ब्लाक के ग्रामीण पिछले कई दशक से बिजली की कटौती से है परेशान। बार-बार शिकायत करने के बावजूद अभी तक समस्या का हल नहीं निकल सका है। लोगों के प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद है।

जनकपुर के कई गांवों में आए दिन अघोषित बिजली कटौती होती रहती है। जिसके विरोध में चांगभखार के ग्रामीणों ने मनेंद्रगढ़ तिराहा में विशाल धरना प्रदर्शन किया। जनकपुर से लगे ग्राम पंचायत कोटाडोल, कुवारपुर, कंजिया , माड़ीसरई बिजली की आंखमिचौली की समस्या दुरुस्त नहीं हो पाई है। ग्रामीणों की माने तो बिजली विभाग के अफसरों को फोन करने पर कोई जवाब नहीं मिलता है। वहीं बारिश के दिनों में जंगली जंतुओं और सांप बिच्छु के कारण ग्रामीणों की मौत हो रही है।

भाजयुमो ने प्रदर्शन को दिया समर्थन- भारतीय जनता युवा मोर्चा ने बिजली की गंभीर समस्या को देखते हुए मनेंद्रगढ़ तिराहा में चक्काजाम किया। ग्रामीणों के साथ जनपद सदस्य रविशंकर सिंह, जनपद उपाध्यक्ष दुर्गा शंकर मिश्रा समेत धरना प्रदर्शन में शामिल हुए। धरना प्रदर्शन के कारण सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई।इस मौके पर पुलिस ने ग्रामीणों को समझाकर जाम खुलवाने की कोशिश की।

जिला पंचायत सदस्य रविशंकर सिंह ने कहा कि चांग भखार में अघोषित बिजली की कटौती को लेकर मनेंद्रगढ़ चौराहे में हम लोग चक्का जाम और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे चांग भखार में बिजली की कटौती एक भयंकर समस्या बनी हुई है। किसान, व्यापारी, ग्रामीण सभी त्रस्त हैं। वहीं इस मामले में जनकपुर बिजली विभाग के जेई ने स्टाफ की कमी का हवाला दिया है। जेई के मुताबिक बारिश के दिनों में आंधी तूफान से लाइन में खराबी आती है। स्टाफ कम है।इसलिए समय लग रहा है। लेकिन बिजली की समस्या को दूर कर लिया जाएगा।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

जमीन विवाद में भिड़े पड़ोसी दोनों पक्षों में जमकर मारपीट

कांकेर। छत्तीसगढ़ के कांकेर में पड़ोसियों में मारपीट हो गई। दोनों पक्षों में जमकर लात-घूंसे चले। इस दौरान महिलाओं से भी छेड़खानी और अभ्रदता की गई। पुलिस ने इस मामले में दोनों पक्षों से 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं एक परिवार पर बलवे का भी मामला दर्ज किया गया है। दोनों पक्षों में जमीन को लेकर पुराना विवाद चला रहा है। इसी को लेकर एक बार फिर उनमें मारपीट हुई है। मामला चारामा थाना क्षेत्र का है। थाना प्रभारी रूपेंद्र पटेल ने बताया कि मुडखुसरा की रहने वाली महिला ने ने मामला दर्ज कराया है कि वह अपने घर के बाड़ी में जा रही थी। इसी दौरान पड़ोस में रहने वाला नरेश साहू उसे देखकर गाली-गलौज करने लगा और छेड़खानी। पुरानी जमीन के रास्ते की बात को लेकर लड़ाई झगड़ा करने लगा। इस पर पुलिस ने नरेश साहू, राजमन बाई, प्रेमलता साहू के खिलाफ मामला दर्ज किया है। वहीं दूसरे पक्ष से एक अन्य महिला ने मामला दर्ज कराया है कि पड़ोस में रहने वाले आरोपी गण एक राय होकर घर में घुस आए और गालियां देने लगे।

ढाबे पर अवैध तरीके से खुलेआम बिक रही शराब

बालोद। बालोद जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग 930 और 30 में संचालित ढाबे पर जमकर अवैध तरीक से शराब बेची जा रहा है। गुरुर थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले इन ढाबों पर खाने के साथ शराब परोशी जा रही है। एक तरफ जिले के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक जहां जिले को अपराध मुक्त बनाने में जुटे हुए हैं तो दूसरी तरफ ये ढाबा संचालक छोटे छोटे कर्मचारियों के दम पर एसपी कलेक्टर से पहचान बताकर जमकर शराब परोस रहे हैं। चिरचारी से शुरू होकर भरदा के दो ढाबा संचालकों ने तो अति मचाकर रख दी है। यहां पर बेतहाशा शराब परोसी जा रही है, हालांकि आबकारी विभाग का दौरा इस क्षेत्र में रहता है। बावजूद इसके यहां पर शराब परोसा जाना समझ से परे हैं। धनोरा के सरपंच ने पुलिस को भी बताया लेकिन परिणाम ये है कि इन ढाबा संचालकों के हौसले और बढ़ते जा रहे हैं। वहीं, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने इन ढाबों पर कार्रवाई की बात कही।

लाखों रुपये के 54 हीरों के साथ दो तस्कर गिरफ्तार

गरियाबंद। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में पुलिस ने शुक्रवार को 54 हीरों के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी हीरे बेचने की फिराक में नेशनल हाईवे पर घूम रहे थे। आरोपियों के पास से बरामद हीरों की कीमत लाखों रुपये में बताई जा रही है। दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। अभी तक यह पता नहीं चल सका है कि आरोपी हीरे कहां से लेकर आए थे। मामला मैनपुर थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक, पुलिस को सूचना मिली कि दो संदिग्ध लोग नेशनल हाईवे 130 सी पर मैनपुर-गरियाबंद के बीच घूम रहे हैं। आरोपियों के पास कोई संदिग्ध सामान हो सकता है। इस पर पुलिस ने एक टीम मौके पर भेजी। मैनपुर से करीब आठ किमी दूर नेशनल हाईवे पर दबनाई नाला के पास दो युवक घूमते दिखाई दिए। इस पर पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया। तलाशी के दौरान उनके पास से 54 हीरे बरामद हुए। इसके बाद पुलिस ने आरोपी विजयवाड़ा भवानीपुर निवासी सैयद हुसैन खान और गरियाबंद निवासी कमाल खान को हिरासत में ले लिया।

297 बोरी पोटाश और 12 बोरी यूरिया बरामद

जगदलपुर। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में पुलिस ने दूसरे राज्य की उर्वरक के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी राजस्थान से ट्रक में उर्वरक लेकर बेचने के लिए पहुंचे थे। ट्रक से पुलिस ने 297 बोरी पोटाश और 12 बोरी यूरिया बरामद की है। इसकी कीमत करीब पांच लाख रुपये से ज्यादा बताई जा रही है। मामला नगरनार थाना क्षेत्र का है। पुलिस ने बताया कि 12 जुलाई को सूचना मिली थी कि 16 चक्का ट्रक में अवैध रूप से उर्वरक खाद को रखकर बिक्री करने के लिए देवडा मंदिर जाने मार्ग रेलवे क्रासिंग के पास खड़ा है। इस पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और घेराबंदी कर ट्रक पकड़ लिया। ट्रक में दो लोग सवार थे। ट्रक की तलाशी लेने पर उसमें दूसरे राज्य की उर्वरक बरामद हुई। ट्रक में सवार आरोपियों ने पूछताछ में अपना नाम-पता राजस्थान के करौली निवासी मीना और हनुमानगढ़ निवासी शिवलाल बताया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 5.25 लाख रुपये कीमत की उर्वरक, दो मोबाइल, 5900 रुपये जब्त किए हैं।

हाईवा और टाटा मैजिक में हुई आमने-सामने की भिड़ंत

जांजगीर चांपा। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले सारागांव ओवरब्रिज के पास हाईवा और टाटा मैजिक वाहन में अपने सामने जोरदार भिड़ंत हुई है। टाटा मैजिक में सवार तीन लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। जिन्हें उपचार के लिए चांपा में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं, मौके से हाईवा चालक वाहन छोड़ कर फरार हो गया है। सारागांव थाना क्षेत्र की घटना है। मिली जानकारी के अनुसार, प्रकाश यादव उम्र 29 वर्ष, तनवर खाना उम्र 44 वर्ष और एक अन्य व्यक्ति तीनो डोडकी गांव के रहने वाले है। तीनों टाटा मैजिक वाहन में सवार होकर सक्ती जिले के डोडकी गांव की तरफ मुर्गी लेने के लिए चांपा की ओर आ रहे थे। तभी चांपा की ओर से जा रही तेज रफ्तार हाईवा वाहन चालक ने सामने से आकर जोरदार ठोकर मारी। जिसे टाटा मैजिक में बैठे तीनों लोग घायल हो गए। जिन्हें उपचार के लिए 108 की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तीनो को गंभीर चोट आई है। जिनका इलाज जारी है।

भटगांव के ग्रामीणों ने सरपंच पर लगाये गंभीर आरोप

■ पंचायत भवन में तालाबंदी करने पहुंचे ग्रामीण

धमतरी। भटगांव में ग्रामीणों ने सरपंच के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया और पंचायत भवन में तालाबंदी करने पहुंच गए। भवन के सामने बड़ी संख्या में ग्रामीण बैठ गए और नारेबाजी करने लगे। मौके पर जनपद सीईओ और पुलिस की टीम मौजूद रही। सीईओ ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही।

सरपंच पर गंभीर आरोप- ग्रामीणों ने सरपंच पर आरोप लगाया कि गांव में सामुदायिक भवन का निर्माण किया जा रहा है। जिसको एक समाज के नाम किया गया है। इसके साथ ही अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने का आरोप ग्रामीणों ने लगाया। राशन कार्ड बनवाने के लिए पैसा लेने और आय और जाति प्रमाण पत्र में साइन करने के एवज में राशि लेने का आरोप सरपंच के ऊपर ग्रामीणों ने लगाया।इस दौरान ग्राम विकास समिति समेत बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।

किसी भी काम के लिए पैसे मांगने का आरोप-ग्राम विकास समिति के अध्यक्ष दूज राम साहू ने बताया कि गांव में कभी भी बैठक होती है तो सरपंच शामिल नहीं होता।

गांव में सामुदायिक भवन निर्माण किया जा रहा है, जिसे देवांगन समाज का नाम दिया जा रहा है। इसी तरह गांव में अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई नहीं की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरपंच द्वारा राशन कार्ड बनवाने वाले ग्रामीणों से रकम ली जाती है। इतना ही नहीं राशन कार्ड आय, जाति प्रमाण पत्र बनवाने या उस पर साइन करने के लिए पैसे मांगे जाते हैं। ग्रामीणों ने भी एक सुर में कहा कि सरपंच द्वारा राशन कार्ड बनवाने के लिए पैसा मांगा जाता है।

सरपंच की सफाई- अपने ऊपर लगे आरोपों पर सरपंच ने सफाई दी है।भटगांव के सरपंच बोधन सिंह ध्रुव का कहना है कि सामुदायिक भवन किसी एक समाज के लिए नहीं है। उनके ऊपर जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वह गलत हैं। पैसा लेने का आरोप भी गलत है। कुछ लोगों द्वारा राजनीति किया जा रहा है। पूरे मामले पर जनपद पंचायत सीईओ ने कहा कि गांव के लोगों ने 4 सूत्रीय मांग को लेकर आवेदन दिया है। जांच के बाद ही कुछ कहा जाएगा।

दुर्ग में महिला आयोग की जनसुनवाई में किन्नर समुदाय ने रखी अपनी मांग

दुर्ग। शुक्रवार को दुर्ग जिला पंचायत सभा कक्ष में महिला उत्पीड़न से संबंधित प्रकरणों पर जनसुनवाई हुई। इस दौरान छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक भी मौजूद रहीं। डॉ किरणमयी नायक की अध्यक्षता में जिले की 19वीं सुनवाई हुई, जिसमें कुल 39 प्रकरणों पर चर्चा हुई। खास बात रही कि इस बार किन्नर समुदायों ने भी महिला आयोग में अपनी मांग रखी।

नकली किन्नर बनकर अवैध वसूली मामला- सुनवाई के दौरान किन्नर समाज दुर्ग द्वारा गौरिया समाज भटगांव के लोगों से अवैध वसूली का शिकायत दर्ज किया गया था। मामले में आयोग द्वारा कोतवाली थाना दुर्ग को निर्देशित किया गया है कि उन्हें पकड़कर उनके खिलाफ उचित कार्रवाई किया जाए। वहीं किन्नर समुदाय की अध्यक्ष जया ने बताया कि कई महिलाएं किन्नर का वेश बनाकर लोगों को लूट रही हैं, जिससे बदनाम किन्नर समुदाय हो रहा है। ट्रेन और दुकानों में जाकर बहुरूपिये अवैध वसूली कर रहे हैं। इसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने की मांग किन्नर समुदाय ने किया है।

सहायक प्रध्यापकों पर सुनाया फैसला- एक और मामले में भिलाई महिला महाविद्यालय की सहायक प्रध्यापकों को 2020 से बहाल कर दिया गया है। साथ ही उनको पुराना वेतन और भत्ता भी दिया गया है। आयोग ने पिछली सुनवाई में कलेक्टर दुर्ग को ट्रस्ट को अपने संरक्षण में लेने का निर्देश दिया गया था। इसके बाद प्रकरण को रद्द किया गया।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

चंद्रयान 3 की सफलता पर फ्रांस से पीएम का बधाई संदेश

नई दिल्ली। चंद्रयान 3 के सफलता पूर्वक लॉन्चिंग पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई संदेश ट्विटर के माध्यम से भेजा है। पीएम मोदी ने भारतीय वैज्ञानिकों की प्रतिभा को सलाम किया है। पीएम मोदी ने शुक्रवार को चंद्रयान 3 के सफलता पूर्वक लॉन्चिंग के बाद ट्विटर पर लिखा, चंद्रयान-3 ने भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक नया अध्याय लिखा। यह हर भारतीय के सपनों और महत्वाकांक्षाओं को ऊपर उठाते हुए ऊंची उड़ान भरता है। यह महत्वपूर्ण उपलब्धि हमारे वैज्ञानिकों के अथक समर्पण का प्रमाण है। मैं उनकी भावना और प्रतिभा को सलाम करता हूँ! वहीं इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा, यह वास्तव में भारत के लिए गौरव का क्षण है और श्रीहरिकोटा में हम सभी के लिए भाग्य का क्षण है, जो बनने वाले इतिहास का हिस्सा थे। भारत को गौरवान्वित करने के लिए टीम इसरो को धन्यवाद और अनलॉक करके इसे संभव बनाने के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद।

कोर्ट ने सिसोदिया की अंतरिम जमानत याचिका पर सीबीआई ईडी से मांगा जवाब

नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के नेता मनीष सिसोदिया की अंतरिम जमानत याचिका पर केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को शुक्रवार को 28 जुलाई तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने सिसोदिया की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी की दलील पर गौर किया जिसमें उन्होंने कहा था कि उनकी पत्नी गंभीर रूप से बीमार हैं और अस्पताल में भर्ती हैं। प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा की पीठ इस मामले पर आज सुनवाई करने के लिए 10 जुलाई को सहमत हुई थी। दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर 2021 को नीति लागू की थी, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच सितंबर 2022 के आखिर में इसे वापस ले लिया गया। सिसोदिया के पास आबकारी विभाग भी था।

केजरीवाल ने 9 साल में कुछ नहीं किया : गौतम गंभीर

नईदिल्ली। दिल्ली में यमुना के जलस्तर में बढ़ोतरी के बाद कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। इसको लेकर राजनीति भी खूब हो रही है। आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच जबरदस्त तरीके से वार-पलटवार का दौर जारी है। इन सब के बीच पूर्वी दिल्ली से सांसद और पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर ने भी अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए साफ तौर पर कहा है कि पिछले 9 सालों में दिल्ली वालों के लिए कुछ नहीं किया गया है। गौतम गंभीर ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए पूछा कि उन्हें बाहर आना चाहिए और बताना चाहिए कि उन्होंने विज्ञापन पर पिछले 9 साल में कितना खर्च किया है और इंफ्रास्ट्रक्चर पर कितने खर्च किए हैं। उन्होंने कहा कि केजरीवाल केवल राजनीति करने में है जबकि हम अपना फर्ज निभा रहे हैं, हम लोगों की सेवा कर रहे हैं। गौतम गंभीर ने कहा कि आज दिल्ली के मुख्यमंत्री लोगों के सामने बेनकाब हो चुके हैं।

अजीत पवार को वित्त और योजना विभाग मिला

मुंबई। महाराष्ट्र के नवनियुक्त डिप्टी सीएम अजीत पवार को वित्त और योजना विभाग मिला है। वहीं कैबिनेट मंत्री छगन भुजबल को खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्रालय दिया गया है। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल विस्तार में, अजीत पवार गुट ने वित्त और योजना, खाद्य और नागरिक आपूर्ति, सहकारी समितियां, महिला और बाल विकास, कृषि, राहत और पुनर्वास और चिकित्सा शिक्षा विभाग हासिल किए। यह विस्तार अजित पवार और आठ राकांपा विधायकों के एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार में शामिल होने के लगभग दो सप्ताह बाद हुआ है। अजित पवार के अलावा उनके गुट की बात करें तो धनंजय मुंडे को कृषि, दिलीप वलसे पाटिल को सहकार, हसन मुश्रीफ को चिकित्सा शिक्षा, छगन भुजबल को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, धर्मराव अत्राम को खाद्य एवं औषधि प्रशासन, अनिल भाईदास पाटिल को खेल और अदिति तटकरे को महिला एवं बाल कल्याण दिया गया है। सत्तारूढ़ शिव सेना-भाजपा गठबंधन में नवीनतम सदस्य राकांपा नेताओं के शामिल होने से विभागों के आवंटन को लेकर खींचतान शुरू हो गई थी।

ओवैसी की पार्टी ने विधि आयोग को सौंपा जवाब

हैदराबाद। समान नागरिक संहिता लागू करने के प्रस्ताव को लेकर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी लगातार केंद्र सरकार पर हमला कर रहे हैं। एक बार उन्होंने केंद्र की एनडीए सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई और चीनी घुसपैठ जैसे मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए यूसीसी की बात की जा रही है। साथ ही ओवैसी ने कहा कि एआईएमआईएम ने विधि आयोग को जवाब सौंपा है। उनकी पार्टी ने यूसीसी पर सुझावों के लिए विधि आयोग की अपील पर इस विषय पर सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश गोपाल गौड़ा की कानूनी राय के साथ अपनी प्रतिक्रिया भेजी है। पत्रकारों से बात करते हुए ओवैसी ने कहा कि वह जल्द ही आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी से मिलकर उनका समर्थन मांगेंगे और उनकी पार्टी से अनुरोध करेंगे कि अगर संसद में ऐसा कोई विधेयक पेश किया जाता है तो यूसीसी के खिलाफ वोट करें।

बिहार में जो लाठीचार्ज किया गया, वह आजाद भारत में निरंकुशता, तानाशाह का एक बड़ा उदाहरण

लाठीचार्ज बिहार सरकार की 'पूर्व नियोजित साजिश': भाजपा

नयी दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने बिहार में जहानाबाद जिले के उसके महासचिव विजय सिंह की बृहस्पतिवार को 'विधानसभा मार्च' के दौरान कथित पुलिस लाठीचार्ज में हुई मौत को राज्य सरकार की 'पूर्व नियोजित साजिश' का नतीजा करार देते हुए शुक्रवार को कहा कि इस मामले में पुलिस की 'बर्बरता' अंग्रेजी हुकूमत की याद दिलाती है। भाजपा मुख्यालय में यहां संवाददाताओं को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने इस हत्याकांड के दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किए जाने और उन्हें सजा देने की मांग करते हुए दावा किया कि राज्य सरकार ने यह साजिश राज्य के लोगों को उनके अधिकारों और न्याय की मांग करने से रोकने के लिए रची थी।

केंद्रीय गृह राज्यमंत्री ने कहा, ''भाजपा कार्यकर्ताओं पर पुलिस का लाठीचार्ज बिहार के लोगों को उनके अधिकारों और न्याय की मांग करने से रोकने के लिए एक पूर्व नियोजित, राज्य प्रायोजित साजिश थी।'' उन्होंने कहा, ''गुरुवार को बिहार में भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर ऐसा लाठी चार्ज किया जैसा कि स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किया था। बिहार में जंगल राज तीन का आगमन हुआ है। बिहार में कल जो बर्बरतापूर्ण लाठी चार्ज किया गया, वह आजाद भारत में निरंकुशता, तानाशाह और बर्बरता का एक बड़ा उदाहरण है।'' राय ने कहा कि भाजपा बिहार सरकार से मांग करती है कि वह किसानों, छात्रों और शिक्षकों के हितों के खिलाफ लिए गए सभी फैसलों को वापस ले। उन्होंने कहा कि भाजपा विजय सिंह की हत्या करने वालों की गिरफ्तारी की भी मांग करती है।

जो काम जनरल डायर ने किया था, वही नीतीश ने किया: सम्राट चौधरी

बिहार में भाजपा की ओर से गुरुवार को विधानसभा मार्च का आयोजन किया गया था। इस मार्च में जबरदस्त हंगामा हुआ। पुलिस और भाजपा कार्यकर्ता आमने-सामने देखे गए। पुलिस ने जबरदस्त तरीके से लाठीचार्ज भी किया। भाजपा का दावा है कि उसके कार्यकर्ता विजय कुमार सिंह की मृत्यु हो गई है। आज भाजपा इसको लेकर ब्लैक डे मना रही है। वही कल की घटना को लेकर भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ एफ आई आर दर्ज कराई गई है। इसी पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि पुलिस को सूचना देने के बाद मार्च किया जा रहा था। एफआईआर क्या, आप जेल भेज दो, गोली मार दो लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा। नीतीश कुमार गुंडाराज करना चाहते हैं।

बिहार में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि हमारी लड़ाई सदन से सड़क तक जारी रहेगी। तेजस्वी यादव सोने की चम्मच लेकर पैदा हुए हैं। उन्हें लोकतंत्र, संवैधानिक संस्था में विश्वास नहीं है। भाजपा विधायक संजय सिंह को मार्शल ने पटना में बिहार विधानसभा से बाहर निकाला। भाजपा विधायक संजय सिंह ने कहा कि मैं गुरुवार की घटना का विरोध कर रहा था। मैं पीठ दिखाकर ये बता रहा था कि देखिए कैसे आपकी सरकार ने हम लोगों पर बर्बरतापूर्ण तरीके से लाठी चलाया। मुझे बस ये दिखाना था कि तुरंत अध्यक्ष ने मार्शल को बाहर करने का निर्देष दिया और मुझे जबरन उठाकर बाहर फेंक दिया गया।

नकारात्मक राजनीति नहीं होनी चाहिए : तेजस्वी यादव

बिहार में राजनीतिक हलचल जबरदस्त तरीके से जारी है। तेजस्वी यादव के खिलाफ दायर चार्जशीट के बाद भाजपा प्रदर्शन कर रही है। तेजस्वी यादव ने भाजपा के दावे को पूरी तरीके से खारिज कर दिया और साफ तौर पर कहा कि नकारात्मक राजनीति नहीं होनी चाहिए। भाजपा के लोग अफवाह फैलाने में माहिर हैं। उन्होंने कहा कि अगर इस तरह का आरोप लगाया जाए तो क्या प्रधानमंत्री पर भी किसान आंदोलन में हुई किसानों की मौतों का आरोप लगेगा? विपक्ष ने तो कभी उनपर ऐसा आरोप नहीं लगाया। राजद नेता ने कहा कि इस तरह की राजनीति देश के लिए और बिहार के लिए सही नहीं है। किसान आंदोलन में कितने लोग मारे गए थे, लेकिन विपक्ष ने तो इस तरह का कोई सवाल नहीं उठाया। इन्होंने सदन चलने नहीं दिया।उन्होंने कहा कि पुलिस ने भी चीजें स्पष्ट कर दी हैं और मृतक के साथ रहे लोगों ने भी स्थिति स्पष्ट कर दी है, इसलिए इस पर कहने को कुछ नहीं है।

जेपी नड्डा ने बनाई 4 सदस्यीय जांच कमेटी, रघुबर दास करेंगे नेतृत्व

भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी कार्यकर्ता की मौत पर एक जांच कमेटी बना दी है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पुलिस लाठी चार्ज में मारे गए पार्टी कार्यकर्ता विजय सिंह की मृत्यु पर गहरा दुख व्यक्त किया है। इसके साथ ही उन्होंने नेताओं एवं कार्यकर्ताओं पर हुई पुलिस प्रशासन की बर्बरता एवं राज्य सरकार के तानाशाही रवैया की घोर निंदा की है। पुलिस द्वारा किए गए इस लाठीचार्ज में कई वरिष्ठ नेता एवं पार्टी कार्यकर्ता घायल हुए हैं। भाजपा ने इस को लेकर एक जांच कमेटी बनाई है जिसका नेतृत्व झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुबर दास करेंगे। इसमें सांसद मनोज तिवारी, विष्णु दयाल राम और सुनीता दुग्गल भी रहेंगे। बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों में विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सदस्यों ने पार्टी के एक नेता की मौत के लिए पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज को जिम्मेदार ठहराया और घटना के विरोध में जबरदस्त हंगामा किया जिसके कारण सदन की कार्यवाही दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र के आखिरी दिन भाजपा सदस्य काला गमछा ओढे और बांहों पर काली पट्टी बांधकर आए थे, उनमें से कुछ ने काला कुर्ता भी पहन रखा था। मार्शलों ने आसन के समीप पहुंचे और वहां एक मेज पर चढ़कर हंगामा कर रहे लालगंज के विधायक संजय कुमार सिंह को बाहर निकाल दिया।

भारत और फ्रांस की स्पेस एजेंसियों के बीच नए समझौते हुए: पीएम मोदी

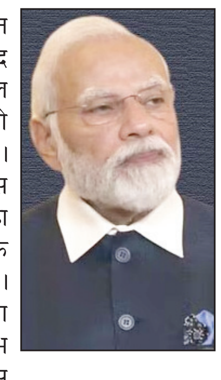

पेरिस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मेंदी इन दिनों फ्रांस में हैं। यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए व्यापक चर्चा की। दोनों दोशों के शीर्ष नेताओं की इस मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने एक प्रेस कांफ्रेंस कर साझा बयान भी दिया। बयान में उन्होंने फ्रांस को रक्षा सहयोग और द्विपक्षीय संबंधों का मजबूत स्तंभ बताया। साथ ही यह भी कहा कि फ्रांस मेक इन इंडिया में भी महत्वपूर्ण साझेदार है। वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शनिवार को संयुक्त अरब अमीरात की एक दिवसीय यात्रा पर रहेंगे। इस यात्रा पर उनका पूरा फोकस ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा और रक्षा क्षेत्र पर होगा।

प्रतिनिधिस्तर की वार्ता के बाद साझा बयान जारी करने के समय पीएम मोदी ने फ्रांस के लोगों को राष्ट्रीय दिवस के लिए शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि यह दिवस विश्व में स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे जैसे मूल्यों का प्रतीक माना जाता है, यह मूल्य दोनों देशों के संबंधों का महत्वपूर्ण आधार है। मुझे खुशी है कि इस अवसर की गरिमा बढ़ाने के लिए भारत की तीनों सेनाओं की टुकड़ियों ने भाग लिया। पीएम ने आगे कहा कि हम अपनी रणनीतिक साझेदारी के 25 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। हम पिछले 25 वर्षों की मजबूत नींव के आधार पर अगले 25 वर्षों का रोडमैप बना रहे हैं। इसके लिए साहसिक एवं महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए जा रहे हैं। भारत के लोगों ने स्वयं को एक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है। इस यात्रा में हम फ्रांस को एक स्वाभाविक भागीदार के रूप में देखते हैं।

रक्षा संबंध भारत और फ्रांस के बीच संबंधों का एक मजबूत स्तंभ

पीएम ने कहा कि रक्षा संबंध भारत और फ्रांस के बीच संबंधों का एक मजबूत स्तंभ और गहरे विश्वास का प्रतीक रहे हैं। प्रेस कांफ्रेंस के दौरान उन्होंने सह-विकास की संभावनाओं के बारे में बात की। साथ ही यह भी कहा कि दोनों देश न केवल खुद की बल्कि अन्य मित्र देशों की आवश्यकताएं भी पूरा करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि भारत और फ्रांस अपने सहयोग को रचनात्मक आकार देने के लिए इंडो-पैसिफिक सहयोग रोडमैप पर काम कर रहे हैं। इंडो-पैसिफिक ट्रांयगुलर डेवेलपमेंट कॉपरेशन फंड के प्रस्ताव पर भी दोनों पक्ष चर्चा में है। इससे पूरे क्षेत्र में स्टार्टअप और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए नए अवसर खुलेंगे।इस दौरान उन्होंने भारत के मिशन चंद्रयान-3 के बारे में भी बात की। पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत में चंद्रयान के सफल लॉन्च पर पूरा भारत उत्साहित है। यह हमारे वैज्ञानिकों की बड़ी उपलब्धि है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत और फ्रांस का पुराना और गहरा सहयोग है। हमारे स्पेस एजेंसियों के बीच नए समझौते हुए हैं।

मार्सिले शहर में खुलेगा भारत का नया वाणिज्य दूतावास

इस दौरान पीएम मोदी ने मार्सिले शहर में एक नया भारतीय वाणिज्य दूतावास खोलने का भी एलान किया। उन्होंने कहा कि हम फ्रांस में पढ़ रहे भारतीय मूल के लोगों को दीर्घकालिक वीजा देने के फैसले का स्वागत करते हैं। मैं फ्रांसीसी विश्वविद्यालयों को भारत में अपने परिसर स्थापित करने के लिए आमंत्रित करता हूं।

आतंकवाद के खिलाफ ठोस कार्रवाई पर बनी सहमति

इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि भारत स्थायी शांति की बहाली में योगदान देने के लिए तैयार है। आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में भारत और फ्रांस हमेशा साथ रहे हैं। हम मानते हैं कि क्रॉस बोर्डर आतंकवाद को समाप्त करने के लिए ठोस कार्रवाई की आवश्यकता है, इस दिशा में दोनों देश सहमत हैं।

खेल
प्रमुख समाचार

सिंधू, सेन क्वार्टर फाइनल में पहुंचे, शंकर भी जीते

काउंसिल ब्लफ्स। दिग्गज बैडमिंटन खिलाड़ी पी वी सिंधू और लक्ष्य सेन ने सीधे गेम में जीत दर्ज करके यहां अमेरिका ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला और पुरुष एकल क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। दो बार की ओलंपिक पदक विजेता तीसरी वरीयता प्राप्त सिंधू ने कोरिया की सुंग शुओ युन को 21-14, 21-12 से हराया। पिछले सप्ताह अपने कनाडा ओपन सुपर 500 खिताब जीतने वाले सेन ने चेक गणराज्य के जेन लोदा को 39 मिनट में 21-8, 23-21 से हराया। सिंधू का अगला मुकाबला चीन की गाओ फांग जी से होगा, जबकि पुरुष एकल में मुकाबला दो भारतीय के बीच होगा। तीसरी वरीयता प्राप्त सेन चेन्नई के 19 वर्षीय एस शंकर मुथुसामी से भिड़ेंगे।

विश्व जूनियर चैंपियनशिप (2022) के रजत पदक विजेता ने प्रभावशाली प्रदर्शन करते हुए इजराइल की मिशा जिल्बरमैन पर 21-18, 21-23, 21-13 से जीत दर्ज की। सिंधु को सुंग के खिलाफ ज्यादा पसीना नहीं बहाना पड़ा। सिंधु ने शुरुआत में ही 7-2 की बढ़त बना ली और फिर इसे 13-5 कर लिया। सुंग ने इस अंतर को 11-14 करने में सफल रही लेकिन सिंधू ने इसके बाद अपने दमदार खेल से उनकी वापसी की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। सिंधू को दूसरे गेम की शुरुआत में सुंग से कड़ी टक्कर मिली। सुंग ने 5-3 की मामूली बढ़त हासिल की लेकिन सिंधू ने इसे 7-7 से बराबर किया और फिर 11-8 की बढ़त ले ली। स्कोर 16-12 होने के बाद सिंधू ने लगातार पांच अंक जुटा कर मुकाबला अपने नाम कर लिया। सेन ने चेक गणराज्य के खिलाड़ी के खिलाफ पहले गेम में अपना दबदबा कायम किया। उन्होंने 6-1 की बढ़त लेने के बाद इसे बढ़ाकर 17-5 कर लिया। इसके बाद उन्हें इस गेम को जीतने में ज्यादा परेशानी नहीं हुई। सेन को हालांकि दूसरे गेम में 39 साल के खिलाड़ी ने कड़ी चुनौती दी।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

सेंसेक्स 66 हजार के पार बंद हुआ, निफ्टी 19564 के पार

नई दिल्ली। घरेलू शेयर बाजार शुक्रवार (14) को एक बार फिर रिकॉर्ड लेवल पर बंद हुआ। इससे पहले सेंसेक्स और निफ्टी नए ऑल टाइम हाई पर पहुंचे। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन सेंसेक्स 502.01 (0.77%) अंकों की बढ़त के साथ पहली बार 66,060.90 अंकों के लेवल पर बंद हुआ। वहीं दूसरी ओर, निफ्टी भी 150.75 (0.78%) अंकों की बढ़त के साथ पहली बार 19,564.50 अंकों के लेवल पर बंद हुआ। टीसीएस के शेयरों में पांच प्रतिशत जबकि टेक महिंद्रा के शेयरों में चार प्रतिशत की वृद्धि दिखी। शुक्रवार को बंधन बैंक ने इस वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही के आंकड़े जारी किए जिसमें कंपनी का प्रॉफिट ऑफ्टर टैक्स पिछली बार के 887 करोड़ के मुकाबले घटकर 721 करोड़ रहा। एक्सचेंज फाइलिंग में बैंक ने बताया कि उसके मुनाफे में 18.7 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई।

8 साल के निचले स्तर पर पहुंची थोक महंगाई दर

नईदिल्ली। खाद्य, ईंधन एवं विनिर्मित उत्पादों की कीमतें कम होने से जून में थोक मुद्रास्फीति की दर में 4.12 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने शुक्रवार को थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति के आंकड़े जारी करते हुए यह जानकारी दी। इसके पहले मई में थोक मुद्रास्फीति दर में 3.48 फीसदी की गिरावट आई थी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, जून में खाद्य उत्पादों की मुद्रास्फीति दर में 1.24 प्रतिशत की गिरावट रही जबकि मई में इसमें 1.59 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि हुई थी। ईंधन एवं बिजली खंड की मुद्रास्फीति जून में 12.63 फीसदी घट गई जबकि मई में इसमें 9.17 प्रतिशत की कमी आई थी। समीक्षाधीन अवधि में विनिर्मित उत्पादों की थोक मुद्रास्फीति में 2.71 फीसदी की गिरावट आई जबकि मई में यह 2.97 फीसदी घटी थी।

गूगल-पे ने भारत में लॉन्च किया यूपीआई लाइट

नईदिल्ली। टेक जाएंट गूगल के पेमेंट ऐप गूगल पे ने गुरुवार को भारत में यूपीआई लाइट फीचर को लॉन्च किया है। इस ऐप के आ जाने से छोटे डिजिटल भुगतान में आसानी होगी। गूगल ने कहा कि गूगल पे यूपीआई लाइट से यूजर्स को तुरंत भुगतान करने के लिए एक दिन में 4,000 रुपये तक जमा करने की सुविधा प्राप्त होगी। साथ ही यूजर्स एक बार में अधिकतम 200 रुपये तक की ट्रांसक्शन बिना यूपीआई पिन डालें कर सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा डिजायन इस फीचर में छोटे भुगतान करने के लिए यूपीआई पिन डालने की जरूरत नहीं होती है। गूगल के उत्पाद प्रबंधन के उपाध्यक्ष अंबरीश केंघे ने कहा कि अनुठी सुविधाएं देश में डिजिटल भुगतान की स्वीकार्यता बढ़ाने के लिए जरूरी हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने यह फीचर सितंबर, 2022 में पेश किया था।

सेनको गोल्ड के शेयरों में 36 फीसदी प्रीमियम पर हुए लिस्ट

नईदिल्ली। आभूषणों की खुदरा विक्रेता कंपनी सेंको गोल्ड ने शुक्रवार को शेयर बाजार में मजबूती के साथ कदम रखा और इसका शेयर निर्गम मूल्य की तुलना में 36 प्रतिशत बढ़त के साथ सूचीबद्ध हुआ। बीएसई पर कंपनी के शेयर ने 431 रुपये के भाव पर कारोबार करना शुरू किया जो इसके 317 रुपये के निर्गम मूल्य की तुलना में 35.96 प्रतिशत अधिक है। थोड़ी ही देर में इसका शेयर 40 प्रतिशत उछलकर 443.80 रुपये के भाव पर भी पहुंच गया। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) में सेंको गोल्ड का शेयर 430 रुपये के भाव पर सूचीबद्ध हुआ जो निर्गम मूल्य की तुलना में 35.64 प्रतिशत अधिक है। कंपनी के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) को पिछले हफ्ते 73.35 गुना अभिदान मिला था। करीब 405 करोड़ रुपये जुटाने के लिए लाए गए आईपीओ के लिए मूल्य दायरा 301-317 रुपये का रखा गया था।

अंतरिक्ष में परचम लहराने की तैयारी

ऋषभ मिश्र

एक जमाने में भारत को सपेरों का देश कहा जाता था, लेकिन अब भारत अंतरिक्ष की दुनिया में एक महाशक्ति बनने की राह पर अग्रसर है। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में अपनी भूमिका को पूरी तरह से बदल दिया है। वर्ष 2014 से पहले जहां भारत में अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़ा सिर्फ एक टेक्नोलॉजी स्पेस स्टार्ट-अप था, वहीं अब ऐसे पंजीकृत स्टार्ट-अप की संख्या 140 तक पहुंच चुकी है। इसके अतिरिक्त भारत में ऐसी कंपनियों की संख्या 400 से ज्यादा हो गई है।

अभी अंतरिक्ष सेवाएं देने के मामले में भारत अमेरिका, चीन, जापान और ब्रिटेन के बाद पांचवें स्थान पर पहुंच चुका है। अभी पूरी दुनिया की स्पेस इकनॉमी लगभग 30 लाख करोड़ रुपये की है, जिसमें भारत की हिस्सेदारी 57,431 करोड़ रुपये की है। लेकिन अगले पांच वर्षों में इसमें सालाना 48 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है, जिससे आगामी पांच वर्षों में भारत की स्पेस इकनॉमी चार लाख 10 हजार करोड़ रुपये की हो सकती है।

भारत के स्टार्ट-अप सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि वे सैटेलाइट और रॉकेट इंजन भी अपने देश में विकसित कर रहे हैं। इनमें से कुछ स्टार्ट-अप ने अगले एक दशक में 30 हजार सैटेलाइट लॉन्च करने का लक्ष्य रखा है। अब ज्यादातर भारतीय स्टार्ट-अप %इनोवेशन% पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। भारतीय स्टार्ट-अप अपनी खुद की रिसर्च (अनुसंधान) और अपने ही देश के काबिल इंजीनियरों के बल पर काम कर रहे हैं। पूरी दुनिया में सबसे काबिल और सस्ते इंजीनियर हमारे इन्हीं स्टार्ट-अप में काम कर रहे हैं। इसलिए दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनियां भारतीय स्टार्ट-अप में निवेश करने के लिए लाइन लगाकर खड़ी हैं।

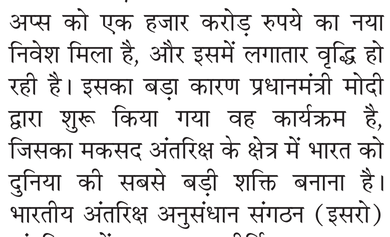

पिछले एक साल में भारत के स्टार्ट-अप्स को एक हजार करोड़ रुपये का नया निवेश मिला है, और इसमें लगातार वृद्धि हो रही है। इसका बड़ा कारण प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू किया गया वह कार्यक्रम है, जिसका मकसद अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत को दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बनाना है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) अंतरिक्ष में नए-नए कीर्तिमान लगातार स्थापित कर रहा है। 2014 से लेकर अब तक इसने 44 स्पेस क्रॉफ्ट मिशन और 42 लॉन्च व्हीकल मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। अब अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी %नासा% भी इसरो के साथ काम करना चाहती है। चंद्रयान-3 पूरी तरह से %मेड इन इंडिया% है। वर्ष 2019 में चंद्रयान-2 की विफलता के बाद यह भारत का तीसरा चंद्रयान मिशन है, जिसे आज आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया जाएगा। चंद्रयान-3 में भी उसी लॉन्चिंग व्हीकल का उपयोग किया गया है, जिसका चंद्रयान-2 में किया गया था। इस यान में कई वैज्ञानिक उपकरण हैं, जो चांद की सतह का अध्ययन करेंगे। इस साल मार्च में इस यान के जरूरी परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे किए गए थे। इसमें चांद पर लॉन्चिंग के दौरान आ सकने वाली संभावित परिस्थितियों का आकलन किया गया था।

चंद्रयान-3 में तीन मॉड्यूल क्रमशः प्रोपल्शन (प्रणोदन), लैंडर तथा रोवर हैं। %प्रणोदन मॉड्यूल% में चांद की कक्षा से पृथ्वी के वर्णक्रमीय और ध्रुवीय माप का अध्ययन करने के लिए %स्पेक्ट्रो पोलरिमेट्रिक ऑफ हैबिटेबल प्लेनेट अर्थ% (एसएचएपीई) नामक उपकरण है, और यह लैंडर तथा रोवर को चांद की कक्षा के 100 किलोमीटर तक ले जाएगा।

इसके अलावा प्रणोदन मॉड्यूल में वैल्यू एडिशन के रूप में एक वैज्ञानिक उपकरण भी है, जिसे लैंडर मॉड्यूल के अलग होने के बाद संचालित किया जाएगा। लैंडर चांद के निर्दिष्ट स्थल पर %सॉफ्ट लैंडिंग% करने और रोवर को तैनात करने की क्षमता से लैस है, जो अपनी गतिशीलता के दौरान चांद का रासायनिक विश्लेषण करेगा। यदि इस बार चंद्रयान-3 का लैंडर चंद्रमा की सतह पर उतरने में सफल हो गया, तो भारत अमेरिका, रूस और चीन के बाद ऐसा कीर्तिमान रचने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा।

बिहार में लोकतंत्र या लाठीतंत्र..!

कुणाल वर्मा

पटना में गुरुवार का दिन इतिहास के पन्नों में काले अध्याय के तौर पर दर्ज हो गया। दरअसल जिस बेरहमी से बिहार पुलिस के जवानों और कमांडो ने बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं, सांसदों, विधायकों पर लाठियों की बौछार कर अपनी मर्दानगी का नमूना दिखाया है उसने अपने आप आने वाले दिनों की रूपरेखा तैयार कर दी है। लाठीचार्ज के दौरान जिला स्तर के एक बड़े नेता की मौत ने बिहार में लाठीतंत्र के नारे को और हवा दे दी है। यह पहली बार नहीं है कि पटना में पुलिस ने बेरहमी से लाठीचार्ज किया है। आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में करीब 12 बार नीतीश कुमार की पुलिस ने अपनी ताकत साबित करने के लिए निहत्थे लोगों पर लाठियां चलाई है। पटना पुलिस और प्रशासन का पूरा अमला गुरुवार को बीजेपी नेता की मौत को सामान्य मौत बताने में जुट गया है। जबकि बीजेपी के सभी बड़े नेताओं का दावा है कि लाठीचार्ज के दौरान ही जहानाबाद के भाजपा नेता विजय कुमार सिंह घायल हो गए थे। घायल अवस्था में उन्हें पहले स्थानीय नर्सिंग होम ले जाया गया, वहां से चिकित्सकों ने मामला गंभीर होने के कारण पटना मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। पीएमसीएच में विजय कुमार सिंह को बचाया नहीं जा सका। उधर पूरा सरकारी तंत्र इस बात को साबित करने में लग गया है कि विजय कुमार सिंह अचेत अवस्था में पाए गए थे। उनके शरीर पर किसी तरह के बाहरी चोट के निशान नहीं हैं। अब पूरी लड़ाई इसी पर होगी कि विजय कुमार सिंह की मौत कैसे हुई। बीजेपी और नीतीश कुमार अंत-अंत तक अपने दावे पर कायम रहेंगे। पर इस सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता है कि जिस तरह बिहार पुलिस ने बर्बरता की सारी हदों को पार किया वह सामान्य नहीं है। आखिर पुलिस को ऐसे क्या निर्देश मिले थे कि उसने सांसदों और विधायकों तक का लिहाज नहीं किया। बीजेपी सांसद का वीडियो वायरल है जिसमें उनके निजी सुरक्षाकर्मी उन्हें बचाने का प्रयास कर रहे हैं और बिहार पुलिस के जवान सांसद की जान लेने पर आमदा हैं। उनके ऊपर ऐसे लाठियां भांजी जा रही हैं जैसे वे कोई आतंकवादी या गैंगस्टर हों। सैकड़ों वीडियो और टीवी के लाइव फुटेज मौजूद हैं जिसमें बिहार पुलिस की बर्बरता को नजदीक से देखा जा सकता है। नीतीश सरकार में यह लाठीचार्ज की कोई पहली घटना नहीं है। एक दिन पहले बुधवार 12 जुलाई को भी किसान सलाहकारों के ऊपर नीतीश कुमार की पुलिस ने जमकर लाठियां चलाई थी। पुलिस वालों ने लोगों को सड़क पर गिरा-गिराकर लाठियां बरसाईं। लाठीचार्ज में कई लोग घायल हुए थे। महिलाओं को भी चोटें आई थी। आंकड़ों की बात करें तो पिछले कुछ सालों में करीब 12 से अधिक बार बिहार के युवाओं को दौड़ा-दौड़ा कर लाठी से पीटा गया है। अभ्यर्थी जब भी अपनी मांगों को लेकर पटना में प्रदर्शन करने पहुंचते हैं पटना पुलिस लाठियों से स्वागत करती है। इसी महीने एक जुलाई को पटना पुलिस ने शिक्षक अभ्यर्थियों पर एक दो बार नहीं बल्कि चार-चार बार लाठी बरसाई थी। सोशल मीडिया में वायरल वीडियो पुलिस की बर्बरता बयां करने को काफी है। गुरुवार 13 जुलाई को दूसरी बार पटना पुलिस ने सभी हदों को पार किया। इससे पहले 22 अगस्त 2022 को दरभंगा से पटना आए शिक्षक अभ्यर्थी को इतना पीटा गया था कि उसकी हालत गंभीर हो गई। अभ्यर्थी हाथ में तिरंगा लिए था, पर उसे पीटते-पीटते अधमरा कर दिया गया। पिटाई का वीडियो वायरल होने पर देश भर में गुस्से की लहर दौड़ गई थी। लाठी भांजने वाले एडीएम पर कार्रवाई की मांग की गई, लेकिन हद तो यह कि वह लाठीबाज एडीएम तरक्की पा गया। उधर, आज भी वह अभ्यर्थी अपने पैरों पर ठीक से खड़ा नहीं हो सका है। बिहार सरकार के लाठीतंत्र पर पहले भी सवाल उठते रहे हैं पर गुरुवार को जो हुआ उसने सभी सीमाओं को तोड़ दिया।

समान नागरिक संहिता विरोधी बैकफुट पर

अजय सेठिया

तुगलक के संपादक एस गुरुमूर्ति के इस लेख ने मुसलमानों में बहस शुरू कर दी है कि भारत में लागू शरीयत क़ानून कुरआन के अनुरूप नहीं है। न सिर्फ कुरआन और हदीसों के मुताबिक़ नहीं है, बल्कि 1937 का यह क़ानून हिन्दुओं और मुसलमानों में बड़ी विभाजन रेखा खींचने के लिए बनाया गया था। उन्होंने लिखा है कि 1937 में शरीयत क़ानून लागू होने से पहले प्रॉपर्टी का उत्तराधिकार, बच्चा गोद लेने या वसीयत के नियम हिंदुओं और मुसलमानों के लिए एक समान थे। यह क़ानून भारत का विभाजन करने के लिए अंग्रेजों की मोहम्मद अली जिन्ना के साथ मिल कर बनाई गई साजिश का हिस्सा था। शरीयत क़ानून की धारा 2 में दस मामलों का जिक्र किया गया है, जिनका फैसला मुस्लिम परंपराओं के अनुसार होगा। इन दस की सूची में बच्चा गोद लेने और वसीयत का जिक्र नहीं है, जबकि इस्लाम में इन दोनों की मनाही है। जिन्ना ने ही अपने व्यक्तिगत कारणों से इन दोनों मुद्दों को मुस्लिम परंपराओं में शामिल नहीं होने दिया। जिन्ना खोजा मुस्लिम थे, जो हिन्दू परम्पराओं का पालन करते हैं, जिनमें गोद लेना और वसीयत भी शामिल हैं।

उस समय अदालतों को यह निर्देश भी दिया गया था कि गोद लेने, वसीयत और विरासत से जुड़े मामलों में अदालतों को अधिनियम की धारा 2 के तहत मुस्लिम कानून लागू करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि ये विषय उक्त धारा में शामिल नहीं हैं। लेकिन शरीयत एक्ट की धारा 3 में प्रावधान है कि अदालतें गोद लेने, वसीयत और विरासत के मामलों में मुस्लिम कानून के नियमों को तभी लागू कर सकती हैं, जब कोई कोर्ट में स्पष्ट तौर पर घोषणा करे कि वह इन मामलों में भी मुस्लिम कानून से फैसला चाहता है। खोजा मुस्लिम कुरआन को नहीं मानते, बल्कि उनका धर्म ग्रंथ दशावतार है, जिसमें नौ अवतार तो हिन्दू हैं, लेकिन दसवां अवतार अली है। यहां एक उदाहरण भी दिया जा सकता है कि जिन्ना की बेटी दीना वाडिया, जिसने अपने पिता की इच्छा के खिलाफ पारसी नेविल वाडिया (नुस्ली वाडिया के पिता) से शादी की थी, वह बंटवारे के बाद भारत में ही रही थी। उसने 2007 में मुम्बई हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी कि जिन्ना के मुम्बई वाले घर पर उसका हक है, क्योंकि कि उनके पिता खोजा शिया थे, इसलिए उन पर विरासत का हिन्दू क़ानून लागू होना चाहिए। ब्रिटिश राज में शुरू शुरू में अदालतें स्थानीय परंपराओं के अनुसार फैसले करती थीं। स्थानीय परंपराओं में महिलाओं को प्रापर्टी में हक नहीं होता था। हालांकि इस्लाम में औरतों को जायदाद में आधा हिस्सा मिलने का रिवाज था, लेकिन भारतीय मुसलमान भी इसी परंपरा को मानते थे। बाद में अंग्रेजों ने तय किया कि हिन्दुओं से संबंधित फैसले हिन्दुओं की परंपराओं, और मुसलमानों से संबंधित फैसले मुस्लिम परंपराओं के अनुसार किए जाएंगे।

1873 के मद्रास सिविल कोर्ट एक्ट और 1876 के अवध लॉज़ एक्ट में लिखा गया कि मज़हबी क़ानून पर स्थानीय परंपरा को तरजीह दी जाएगी। मुसलमानों के मुकद्दमों का फैसला करने के लिए अदालतें इस्लामिक मौलवियों का सहारा लेती थीं, बाद में अंग्रेजों ने तय किया कि वे मुल्ला मौलवियों का सहारा लेने की बजाए हदीसों और इस्लामिक परंपराओं पर आधारित क़ानून बनाएंगे। राजनीतिक प्रोजेक्ट के तहत चार्ल्स हैमिल्टन से हदीसों और इस्लामिक परंपराओं पर आधारित किताब लिखवाई गई, जिसका नाम था अल हादिया। जो अंग्रेज़ हिंदुस्तान आकर वकालत करना चाहते थे, उनके लिए इस किताब को पढ़ना जरूरी कर दिया गया था। बाद में बनाया गया मुस्लिम पर्सनल लॉ इसी किताब पर आधारित है। पर्सनल लॉ को कोडिफाई नहीं किया गया है, बस इतना लिख दिया गया कि दोनों पक्ष मुस्लिम हों, तो शादी, तलाक़, जायदाद, विरासत से जुड़े दस मुद्दों का फैसला शरीयत के हिसाब से होगा, वरना देश का सामान्य क़ानून लागू होगा। आज़ादी के बाद भारत की संविधान सभा सभी पर्सनल एक्ट को खत्म करके समान नागरिक संहिता बनाना चाहती थी, डा. भीमराव अंबेडकर ने समान नागरिक संहिता की जमकर वकालत की थी। उन्होंने संविधान सभा में मुस्लिम लीग के उन सदस्यों की आलोचना की थी जिन्होंने समान नागरिक संहिता के खिलाफ यह कहते हुए बहस की थी कि शरिया मुसलमानों के लिए लाजिमी है।

डा. अंबेडकर ने शरिया को लाजिमी बताने वालों को बताया था कि अगर यह मुसलमानों के लिए लाजिमी है, तो 1937 तक हिंदू कानून का पालन क्यों हो रहा था। 1937 तक संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत और बॉम्बे में भी उत्तराधिकार के मामलों में फैसले हिंदू कानून के मुताबिक़ तय होते थे। लेकिन पंडित जवाहर लाल नेहरू की रहनुमाई में कांग्रेस के नेताओं ने अंग्रेजों की तरह धर्मों की परंपराओं के मुताबिक़ क़ानून पर जोर दिया। नतीजतन अंग्रेजों का हिन्दू-मुस्लिम में फूट डालने के लिए बनाया गया मुस्लिम पर्सनल एक्ट जस का तस रह गया। संविधान सभा में यह सहमति हुई कि अनुच्छेद 44 में यह लिखा जाए कि आने वाली सरकारें भारत में सभी को मान्य समान नागरिक संहिता बनाएगी। सुप्रीमकोर्ट और अनेक हाईकोर्ट सरकारों को याद दिलाते रहे हैं कि समान नागरिक संहिता लागू करना है, लेकिन मुस्लिम तुष्टिकरण और वोट बैंक के कारण कांग्रेस और कांग्रेस समर्थित सरकारें अदालतों के निर्देशों की अनदेखी करती रही। जबकि समान नागरिक संहिता को लागू करना हमेशा से भाजपा के चुनाव घोषणा पत्र में रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में सरकार बनने पर भी 21वें विधि आयोग को इस विषय पर काम करने की जिम्मेदारी दी थी, और अब 22वें विधि आयोग को भी दी जिम्मेदारी दी हुई है। आयोग पिछले तीन साल से इस विषय पर काम कर रहा है। अब अपने काम में तेजी लाते हुए आयोग ने 14 जुलाई तक लोगों से सुझाव मांगे हैं। मोदी सरकार लोकसभा चुनावों से पहले समान नागरिक संहिता का बिल पास करवाने के मूड में है। हो सकता संसद के मॉनसून सत्र में ही एक बिल पेश किया जाए और सभी दलों के सांसदों में आम राय बनाने के लिए गृह मंत्रालय की स्थाई समिति में भेज दिया जाए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपना विरोध जता दिया है, मुस्लिम समुदाय ने जिस आधार पर संविधान सभा में विरोध किया था, उनका विरोध आज भी उसी आधार पर है।

उनका तर्क है कि पर्सनल लॉ उनकी धार्मिक स्वतंत्रता और सांस्कृतिक पहचान का एक अभिन्न अंग हैं, समान संहिता लागू करने से उनके अधिकारों का उल्लंघन होगा और उनकी विशिष्ट पहचान पर बुरा असर होगा। लेकिन राजनीतिक दलों में समान नागरिक संहिता का विरोध उस तरह नहीं हो रहा, जैसे समूचे विपक्ष ने नागरिकता संशोधन क़ानून का किया था, सभी राजनीतिक दल बिल के प्रारूप का इन्तजार कर रहे हैं। इसकी एक वजह यह भी है कि मुस्लिम महिलाएं बड़ी तादाद में उसी तरह समान नागरिक संहिता का समर्थन कर रही हैं, जैसे तीन तलाक बैन करने का समर्थन किया था। मुस्लिम महिलाएं लंबे समय से मुस्लिम पर्सनल लॉ को कोडिफाइड करके मुस्लिम फैमिली क़ानून लाने की मांग करती रही हैं। लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर हावी लोग इसकी जरूरत नहीं समझते, इसलिए अब बदलाव की मांग करने वाली मुस्लिम महिलाएं खुल कर समान नागरिक संहिता के पक्ष में बोलने लगी हैं। मुस्लिमं महिलाएं चाहती हैं कि शादी के लिए उम्र 18 और 21 साल जो सबके लिए है वह मुस्लिमों के लिए भी हो। जबकि इस्लाम कहता है कि 13 साल की बच्ची शादी करने लायक हो जाती है। ष्ट्ठ आसान नहीं है समान नागरिक संहिता की राह जब इस्लाम में शादी एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है तो 13 साल की बच्ची इस काबिल कैसे हो सकती है कि वह सोशल कॉन्ट्रैक्ट को समझे। मुस्लिम महिलाएं इस मांग के लिए भी लंबे समय से लड़ रही हैं कि बिना पहली पत्नी की सहमति के मर्द को दूसरी शादी की इजाजत नहीं होनी चाहिए। इसी तरह 21वीं सदी में चार शादियों की इजाजत खत्म होनी चाहिए, वह जमाना अलग था, जब चार चार शादियों की इजाजत थी।

भारतीय ज्ञान परंपरा....

त्रिशिखिब्राह्मणोपनिषद् (भाग-7)

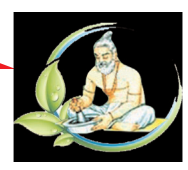

गतांक से आगे...

कन्द से नीचे की ओर पैर के अँगूठे तक कौशिकी नामक नाड़ी गयी हुई है। ये दस नाड़ियाँ कन्द से निःसृत हुई कही गयी हैं। उनके मूल से निकलने वाली अन्य बहुत-सी स्थूल एवं सूक्ष्म नाड़ियाँ हैं, जिनकी संख्या कुल मिलाकर बहत्तर हजार बतलायी गयी है। इन स्थूल एवं सूक्ष्म नाड़ियों की अलग-अलग गिनती कर सकना बहुत ही कठिन है। वे सब उसी प्रकार फैली हुई हैं, जिस प्रकार पीपल के पत्ते में स्थूल सूक्ष्म नसें फैली होती हैं।

प्राण अपान, समान, उदान, व्यान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनञ्जय-ये दस प्राण भी नाड़ियों में विचरण करते रहते हैं। इनमें प्राणादि प्रथम पाँच मुख्य हैं, जिनमें से दो (प्राण अपान) प्रधान हैं।

अथवा प्राणवायु ही सबसे प्रमुख है, जो जीव को धारण किये रहता है। हे द्विज श्रेष्ठ! मुख्य प्राण के प्रधान निवास स्थान पाँच बतलाये गये हैं- जिनमें मुख एवं नासिका का मध्य भाग, हृदय, नाभि मण्डल एवं पैर का अंगूठा है। हे ब्रह्मन। अपान वायु-गुदा, मेढ्र, जंघा एवं घुटने में विचरण करता है। समान वायु शरीर के समस्त अंगों में संव्याप्त रहता है तथा उदान चारों हाथ-पैरों एवं समस्त संधि-जोड़ के स्थानों में प्रतिष्ठित है। व्यान नामक वायु-श्रोत्र, जंघा, कमर, एड़ी, कन्धे एवं गले में निवास करता है और नाग आदि पाँच उपवायु त्वचा, अस्थि (हड्डी) आदि में प्रतिष्ठित रहते हैं।

प्राणवायु आमाशय में स्थित जल, अन्न एवं रस आदि को सर्वप्रथम एकत्र करता है। तत्पश्चात् उसी के बीच में पृथक् पृथक् स्थापित करता है। इन समस्त कार्यों को प्राणवायु अलग स्थित होकर करता है। मल एवं मूत्रादि के विसर्जन का कार्य अपान वायु द्वारा सम्पन्न होता है। प्राण, अपान आदि वायु की चेष्टाएँ व्यान वायु के योग से सम्पन्न की जाती हैं तथा शरीर में विद्यमान उदान वायु के द्वारा नभोगामी (ऊर्ध्वगामी) हुआ जाता है। शरीर का पालन-पोषण सर्वदा समान वायु के द्वारा सम्पन्न होता है। डकार आदि की क्रिया नाग-वायु के द्वारा होती है और नेत्रों का खोलना एवं बन्द करना कूर्म वायु का कार्य होता है। कृकल - वायु का कार्य भूख लगना है। देवदत्त वायु के द्वारा निद्रा आदि तथा मृत शरीर की शोभा (मृत्यूपरान्त कुछ समय तक अविकृत रहना) आदि धनञ्जय वायु का कार्य कहा गया है। हे द्विज श्रेष्ठ! नाड़ी, वायु, प्राणों के स्थान तथा चेष्टाएँ नाना प्रकार की हैं। उन सभी को जानने का प्रयास करना चाहिए।

क्रमशः ...

विश्व युवा कौशल दिवस

प्रदीप कुमार सिंह

विश्व युवा कौशल दिवस की स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 11 नवम्बर 2014 को श्रीलंका के प्रस्ताव पर की गयी थी। महासभा ने 15 जुलाई को प्रतिवर्ष विश्व युवा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। संयुक्त राष्ट्र ने विश्व के सभी देशों से यह आग्रह किया कि वे अपने देश में युवाओं को कौशल विकास में सहायता प्रदान करें ताकि ये युवा आगे चलकर बेहतर राष्ट्र तथा विश्व के निर्माण में योगदान दे सकें। 21वीं सदी की युवा पीढ़ी सारे विश्व में घूम-घूमकर अपनी सर्वोत्तम प्रतिभा का प्रदर्शन कर रही है। इनोवेशन की 21वीं सदी में वसुधैव कुटुम्बकम् की अवधारणा साकार रूप लेने की ओर से तेजी से बढ़ रही है।

संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित यह महत्वपूर्ण दिवस तकनीकी, व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए कौशल के विकास के महत्व पर अधिक जागरूकता और विश्व बन्धुत्व की भावना विकसित करने के लिए प्रयासरत है। यह उम्मीद की जाती है कि यह दुनिया भर के युवाओं के लिए युगानुकूल कौशल तथा उसके अनुरूप रोजगारों में वृद्धि करने में योगदान देगा। इस दिवस पर न्यूयार्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय और

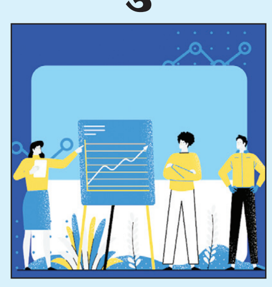

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जहां विभिन्न देशों के युवा विज्ञान, कला और प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में अपने उच्चतम कौशल को दिखाने के लिए एकत्रित होते हैं।

संसार को आश्चर्यचकित कर देने वाले युवा संन्यासी स्वामी विवेकानंद अध्यात्म एवं विज्ञान में समन्वय एवं आर्थिक समृद्धि के प्रबल समर्थक थे। हम सभी भारतवासी 12 जनवरी को युवा स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष धूमधाम से मनाते हैं। 'उठो, जागो और तब तक मत रूको जब तक मंजिल प्राप्त न हो जाए' का संदेश देने वाले स्वामी विवेकानंद थे। स्वामी जी ने युवाओं से कहा कि जीवन में एक विचार लें उस विचार को अपनी जिंदगी बना लें। उसके बारे में सोचिये, उसके सपने देखिये, उस विचार के लिए, आपका मन, आपकी मांसपेशियां, आपके शरीर का हर एक अंग, सभी उस विचार से भरपूर हो और दूसरे सभी विचारों को छोड़ दे। यही उच्चतम सफलता पाने का सबसे बेहतर तरीका हैं। उन्होंने सन् 1897 में युवाओं को संबोधित करते हुए कहा था जगत में बड़ी-बड़ी विजयी जातियां हो चुकी हैं। हम भी महान विजेता रह चुके हैं। हमारी विजय की गाथा को महान सम्राट अशोक ने धर्म और आध्यात्मिकता की ही विजय गाथा बताया है। अब समय आ गया है कि भारत फिर से वैज्ञानिक अध्यात्म के बलबूते 'जगत गुरु' के रूप में राह से भटके विश्व का पथ प्रदर्शन करे।

भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक तथा युवा देश है। भारत की लगभग 65 प्रतिशत जनसंख्या की आयु 14 वर्ष से लेकर 40 वर्ष से कम है। यह एक ऐसा वर्ग है जो शारीरिक एवं मानसिक रूप से सबसे ज्यादा ताकतवर है। इसका कारण यह है कि हमारे देश की परम्परा योग और अध्यात्म की रही है। योग और अध्यात्म की परम्परा में पले-बढ़े देश के युवा अपने परिवार, समाज, देश तथा विश्व के विकास के लिए हर संभव प्रयत्न कर रहे हैं। आज भारत का युवा अध्यात्म तथा विज्ञान के समन्वय के बलबुते विश्व में हर क्षेत्र में उच्चतम ऊंचाईयों को छू रहा है।

प्रगतिशील सोच और ज्ञान विज्ञान पर सुनियोजित हमला

नीरज मनजीत

हफ़्ते भर से ज़्यादा दिनों तक इकतरफ़ा दंगों की आग में झुलसते फ्रांस में फ़िलहाल अमन क़ायम हो गया है। उम्मीद की जानी चाहिए कि यह अमन स्थायी साबित होगा। इन दंगों को इकतरफ़ा इसलिए कहा जा रहा है, क्योंकि यह दो संप्रदायों के बीच का संघर्ष नहीं था, वरन एक मजहब के उन्मादी कट्टरपंथियों का योजनाबद्ध तरीके से किया गया उपद्रव था। इस अनपेक्षित घटना ने दुनियाभर के प्रबुद्धजनों को जितना विस्मित किया है, उससे कहीं ज़्यादा स्तब्ध और फ़िक्रमंद किया है। ये दंगे उदारवाद, लोकतंत्र, प्रगतिशील सोच और ज्ञान-विज्ञान पर किए गए सुनियोजित हमले हैं। किसी विशेष एजेंडे के पक्ष में लिखने वाले लोगों ने इन दंगों को अमीर-गरीब या श्वेत-अश्वेत के संघर्ष अथवा पार्टियों की राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के नज़रिए से इसकी व्याख्या करके जिम्मेदार मजहबी कट्टरवादियों को कवर देने की कोशिश की है, मगर वे नितांत विफल साबित हुए हैं। यदि भारत में ऐसी कोई घटना होती तो इस नैरेटिव पर यकीन करने वाले बहुत से लोग मिल जाते। इसलिए कि हमारे यहाँ वोट बैंक की राजनीति और राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के चलते अक्सर ऐसी घटनाएँ होती रहती हैं।

दरअसल मजहबी उग्रवाद के एंगल से इन दंगों का विश्लेषण किया जाना जरूरी है, क्योंकि यह उन्माद एक ग्लोबल ख़तरे के रूप में हमारे सामने आ खड़ा हुआ है। एक पुलिसमैन की गोली से अल्जीरियाई किशोर नेहाल की मौत लॉ एंड ऑर्डर की सख़्ती का मामला हो सकता है, जिसके लिए तत्काल उस पुलिसमैन को बर्ख़ास्त करके जाँच बिठा दी गई थी। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रां ने माफ़ी माँगते हुए इस शूटआउट को अक्षम्य करार दिया

था। हालाँकि ज़्यादातर पुलिस संगठनों ने राष्ट्रपति की इस बात से नाइत्तिफ़ाक़ी जताते हुए इसकी ख़िलाफ़त भी की थी। यह अजीब बात है कि इन दंगों को गै़रवाजिब न ठहराने की कोशिश में फ्रांस की कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ लोगों ने नेहाल को मासूम बताते हुए फ्रांस की समूची व्यवस्था को ही कठघरे में खड़ा कर दिया है। मानवीय दृष्टिकोण से नेहाल को सही ठहराने की कोशिशों को ग़लत नहीं माना जा सकता। मगर इस घटना की प्रतिक्रिया में एक खास मजहब के हजारों उपद्रवियों ने जिस तरह से पूरे फ्रांस को जलाने की कोशिश की है, उसे कैसे माफ़ किया जा सकता है। फ्रांस के अलावा जर्मनी, बेल्जियम, स्वीडन और स्विट्जरलैंड में भी ये आग फैलती दिखाई पड़ी है। ये सभी देश फ्रांस के पड़ोसी हैं। पोलैंड फ्रांस से ज़्यादा दूर नहीं है, किंतु वहाँ इस आग का कोई असर नज़र नहीं आया। वजह थी अप्रवासियों के प्रति पोलैंड सरकार का सख़्त रवैया, जिसके तहत पोलैंड की सीमाएं सील कर दी गई हैं और मजहबी उग्रवादियों के लिए पोलैंड में कोई जगह नहीं है।

इन उपद्रवी उग्रवादियों में सीरिया और मोरक्को के गृहयुद्ध से त्रस्त होकर फ्रांस आए रिफ्यूजियों की तादाद ज़्यादा थी। दंगाग्रस्त शहरों के आसपास उपनगरों में रहने वाले अश्वेत और गरीब अप्रवासी भी इस गुंडागर्दी में शामिल थे। इन सारे लोगों को फ्रांस के संविधान के मुताबिक सरकार से सारे फ़ायदे मिल रहे हैं। इन्हें बसाने का लिए उपनगरीय इलाकों में घर बनाए गए हैं। यह बताने की जरूरत नहीं है कि फ्रांस एक खुले दिलोदिमाग़ का पूरी तरह सेक्युलर प्रगतिशील देश है, जो मानवाधिकारों को संवैधानिक रूप से तरज़ीह देता है। इन्हीं नीतियों के तहत फ्रांस सरकार ने खुले दिल से अरब और अफ्रीकी मूल के रिफ्यूजियों का स्वागत किया था और उन्हें इज़्ज़त से शरण दी थी। उन्हें बसाने के लिए उन्होंने अपनी आव्रजन नीतियों को शिथिल करते हुए उदारवादी रुख अपनाया था। ऐसा उन्होंने विशुद्ध मानवीय संवेदनाओं के आधार पर किया था। किसी वोटबैंक से मिलने वाले थोक वोटों के लिए उन्होंने ऐसा नहीं किया था। भारत में तो वोट के लालच में बिना किसी जाँच के ग़ैरकानूनी तरीक़े से पड़ोसी देशों के गुंडों को बसा दिया जाता है।

फ्रांस जैसे हर सभ्य सेक्युलर प्रगतिशील देश का विचार यही रहता है कि उदारवादी तौर तरीकों से किसी शख़्स की कट्टरवादी उग्रवादी सोच बदली जा सकती है। उसे सभ्य नागरिक के रूप में वैश्विक मुख्यधारा में लाया जा सकता है। मगर अफ़सोस कि फ्रांस की इन घटनाओं ने उदारवादी लोकतांत्रिक मूल्यों को ध्वस्त करके यह जता दिया है कि उनके दिलोदिमाग में मजहबी कट्टरता की जड़ें काफी गहरी हैं। यूरोप का अल्ट्रा लेफ़्टिस्ट ग्रुप भले ही कैसे भी तर्क देकर उन्हें कवर दे रहा हो, पर इन दंगों के बीच फ्रांस की ऐतिहासिक मार्सेली लायब्रेरी को जब इन उपद्रवियों ने आग में झोंका, तो उन्हें पूरी तरह पहचान लिया गया। ये वही 1400 साल पीछे की कट्टर मजहबी मानसिकता है, जो ज्ञान विज्ञान की दुश्मन है और पृथ्वी को गोल न मानकर चपटा मानती है। दुनिया को ज़हालत के अँधेरे में धकेलने की चाहत रखने वाली ये वही मजहबी कट्टरता है, जिसके असर में 1183 ईस्वी में आक्रांता बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय के विशाल पुस्तकालय को आग के हवाले कर दिया था।

अब तो आलम यह है कि मजहबी कट्टरता ने खेलों के इलाक़े में भी कदम रख दिए हैं। पिछले साल दिसंबर में विश्वकप फुटबाल चैंपियनशिप में मोरक्को ने जब पुर्तगाल को हराकर सेमीफ़ाइनल में जगह बनाई थी, तो ऐसे ही लोगों ने इसे एक ख़ास मजहब की जीत बताकर ज़हर घोलने की कोशिश की थी। पाकिस्तान की ख़ुफ़िया एजेंसी आईएसआई विषवमन के इस खेल में सबसे आगे थी। जब सेमीफ़ाइनल में फ्रांस ने मोरक्को को हरा दिया, तो मोरक्को के समर्थक हिंसा करने और भड़काने पर उतारू हो गए थे। दो साल पहले दुबई में विश्वकप क्रिकेट के दौरान भारत पर पाकिस्तान की जीत को वहाँ के एक वज़ीर ने मजहबी जीत बताकर ज़हर फैलाया था।

बापू की दिनचर्या

सायंकालीन प्रार्थना (भाग-4)

गतांक से आगे...

यह देखकर बापू को दुःख होता। सो, उन्होंने कुरान की आयतें शुरू में पढ़ने का नियम बना दिया और प्रार्थना के बड़े समुदाय में से किसी के द्वारा विरोध करने पर वे प्रार्थना ही बंद कर केवल प्रवचन करते। एक बार एक भाई ने बापू की सायंकालीन प्रार्थना सभा का बहुत मार्मिक चित्रण इन शब्दों में किया था-प्रार्थना के समय विशाल क्षेत्र के खुले प्रांगण में, वर्तुलाकार रेती पर जनसाधारण और आश्रम निवासियों के बीच, एक छोटे-से लकड़ी के पटरे के सहारे बैठे बापू ऐसे मालूम होते, मानो ग्रंथों में वर्णित वैदिक युग का कोई ऋषि अपनी शिष्यमंडली के साथ आसीन हो। प्रार्थना की घंटी बजते ही जब अपने-अपने कार्यों में दक्ष, भिन्न-भिन्न प्रदेश, जाति और देश के लोग प्रार्थना स्थल की ओर दौड़ते, तब ऐसा प्रतीत होता, मानो कोई महामानव सबको अपने में मिला लेने का आह्वान कर रहा हो। मानो रवींद्रनाथ के शब्दों में कह रहा हो- ऐ हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, पारसी, ईसाई और अंग्रेज-तुम सब आओ। मनुष्यों का महासागर भारत तुम सबका स्वागत करता है और फिर रात्रि की निस्तब्धता में साथ लाई हुई लालटेनों का प्रकाश भी जब मद्धिम कर दिया जाता, तब सचमुच रूप और रंग से परे उस मनुष्यों के समुदाय में अपने अधखुले बदन पर श्वेत खादी वस्त्रों के बीच, सत्य व शांति के आशीर्वाददाता की तरह, पालथी मारे शांत, अडिग, ध्यानस्थ और स्थितप्रज्ञ बापू ऐसे लगते, मानो साक्षात् बुद्ध हों। आश्रम में सूत कातना सब के लिए अनिवार्य था। दिन भर में काते गए सूत के तारों का हिसाब सायंकालीन प्रार्थना के बाद लिखाया जाता। यही उपस्थिति समझी जाती।

संक्षिप्त समाचार

मुख्यमंत्री ने चंद्रयान-3 के सफल प्रक्षेपण पर इसरो को दी बधाई

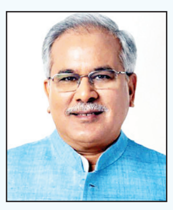

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने चंद्रयान-3 के सफल प्रक्षेपण पर ट्वीट कर इसरो सहित सभी देशवासियों को बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि चंद्रयान-3 का सफल प्रक्षेपण हमारे वैज्ञानिकों की मेहनत, समर्पण और भारत की शक्ति का प्रमाण है। इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर इसरो सहित सभी देशवासियों को बधाई। आज हमारे वैज्ञानिकों ने हम सब का सिर गर्व से ऊंचा किया है।

गोधन न्याय योजना से बढ़े आय और रोजगार के अवसरः मुख्यमंत्री बघेल

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल से आज शाम यहां उनके निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ झेरिया यादव समाज के प्रतिनिधिमंडल ने सौजन्य मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री से प्रतिनिधिमंडल ने सामाजिक विषयों पर चर्चा की और सभी वर्गों के लोगों के उत्थान के लिए राज्य में संचालित जनकल्याणकारी कार्यक्रमों के लिए उनका आभार जताया। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के दौरान अवगत कराया कि छत्तीसगढ़ में यादव समाज खेती-किसानी के साथ-साथ पशुपालन से भी जुड़े हुए है। राज्य में हमारी सरकार द्वारा गोधन न्याय योजना संचालित की जा रही है। इससे सभी गौपालकों सहित यादव समाज के जीवन में काफी बदलाव आ रहा है। छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना को हम एक मिशन के रूप में संचालित कर रहे है। योजना के तहत हमने गांव-गांव में भूमि को आरक्षित कर गौठानों का निर्माण किया। साथ ही अब गौठानों को ग्रामीण औद्योगिक पार्क के रूप में उन्नत किया जा रहा है। इससे गांवों में आय के साथ-साथ रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं।इस अवसर पर प्रतिनिधिमंडल में श्री गणेश गौ सेवक, श्री लोमश यदु, श्री मन्नू लाल यादव, श्री सूरज यादव तथा श्री शिवराम यादव आदि उपस्थित थे।

कांग्रेस जितना भी परिवर्तन करे, जनता ने भी परिवर्तन का मन बना लिया है: साव

गौरेला पेंड्रा मरवाही। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव गुरुवार को एक दिवसीय दौरे पर पेण्ड्रा पहुंचे, यहां उन्होंने गौरेला में भारत सरकार के उपक्रम नेहरू युवा केन्द्र द्वारा आयोजित युवा उत्सव कार्यक्रम में शिरकत किया। साव यहां पंडित माधवराव सप्रे प्रेस क्लब पहुंचे, जहां पर माधवराव सप्रे की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। जिसके बाद प्रेस क्लब में स्थानीय पत्रकारों से चर्चा की है। इस मौके पर अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस में इन दिनों परिवर्तन का दौर चल रहा है। टीएस सिंहदेव, जो मुख्यमंत्री बनना चाह रहे थे, उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया गया। उसके बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष को बदला गया। आगे भी कुछ बदलाव के संकेत दिख रहे हैं। प्रदेश की जनता ने भी परिवर्तन का मन बना लिया है, इसलिए कांग्रेस डरी हुई है, घबराई हुई है। कांग्रेस जितना भी परिवर्तन कर ले, जनता ने राज्य की कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने का मन बना लिया है। बता दें कि चुनाव नजदीक होने के कारण लगातार भाजपा के बड़े नेताओं का प्रदेश में दौरा चलता रहेगा। इस बात की जानकारी अरुण साव ने दी है।

तीजनबाई की तबियत बिगड़ी, मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को दिया निर्देश

रायपुर। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध लोक कलाकर और पंडवानी गायिका तीजन बाई की तबियत गुरुवार को अचानक बिगड़ गई है। दस दिन पहले उन्हें पैरालिसिस का अटैक आया था। उसके बाद सेक्टर-9 अस्पताल में इलाज हुआ। तीजन बाई की तबीयत पहले से ठीक हैं। दो बेटों के निधन के बाद से ही तीजन बाई का स्वास्थ्य खराब चल रहा था। इसके बाद उन्हें पैरालिसिस की शिकायत भी हुई। सीएम ने तीजन बाई का ध्यान रखने के दिये निर्देश- मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पद्मविभूषण तीजन बाई की तबियत खराब होने की सूचना मिलने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मामले को तत्काल संज्ञान में लिया। सीएम के संज्ञान में लेने के बाद डॉक्टरों की टीम तीजन बाई के घर पहुंची और उनका जांच किया। मुख्यमंत्री बघेल ने जिला प्रशासन को तीजन बाई की सेहत का पूरा ध्यान रखने के निर्देश दिए हैं। सीएमओ ने इस इसकी जानकारी आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर दी है। पंडवानी में दुशासन वध के प्रसंग पर तीजन का पॉवरफुल प्रदर्शन सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। वहीं तीजन की लोकप्रियता छत्तीसगढ़ के साथ-साथ दूसरे राज्यों में भी है। 1980 में तीजन बाई ने सांस्कृतिक राजदूत के रूप में इंग्लैंड, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी, टर्की, माल्टा, साइप्रस, रोमानिया और मॉरीशस की यात्रा की। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पंडवानी गायिका डॉ तीजन बाई को साल 1988 में पद्मश्री सम्मान मिला। 1995 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

मोदी युवाओं को सक्षम बनाने लगातार प्रयासरत हैंः सौरभ सिंह

■ **अकलतरा में आरके सिंह स्कूल में जी-20 के यूथ विंग वाय-20 की ऐतिहासिक बैठक**

जांजगीर/चांपा। भारत की अध्यक्षता में हो रहे जी-20 बैठक के महत्वपूर्ण हिस्सा वाय-20 की एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन जांजगीर-चांपा जिले के अकलतरा स्थित राजेंद्र कुमार सिंह उच्चतर माध्यमिक शाला में शुक्रवार को प्रारंभ हुआ। बता दें कि वाय-20, जी-20 का युवा विभाग है। जिसके तहत दुनिया भर के विशेषज्ञ भारतीय युवाओं को लीडरशिप की ट्रेनिंग देने के लिए देश के विभिन्न हिस्से में जा रहे हैं। इसी के तहत आईआईएम के प्रो. संजीव पाराशर ने ओजस्वी वक्तव्य प्रस्तुत किया।

उन्होंने कहा कि आने वाला वक्त भारत का है। भारत ने गत 9 वर्ष में कई उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की है। पहले विश्व की अर्थव्यवस्था में भारत का स्थान 10वां था जो अब पांचवें पायदान पर पहुंच चुका है। उन्होंने महाभारत का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत के हर युवा को अपना राजधर्म समझना होगा। प्रो. पराशर ने प्रधानमंत्री के आह्वान को आत्मसात करने की अपील करते हुए सभी से वसुधैव कुटुम्बकम् के भाव को अपनाने की अपील की। इससे पहले अकलतरा के विधायक सौरभ कुमार सिंह ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि अकलतरा जैसी जगह पर वाय 20 के कार्यक्रम के आयोजन का मूल उद्देश्य यहां के नौनिहालों को दुनिया की जानकारियों से अवगत कराना है। विधायक ने सभी प्रतिभागियों से विभिन्न सत्रों में दी जा रही जानकारियों को आत्मसात करने की अपील की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सदैव इस बात को लेकर काम करते रहते हैं कि देश के युवाओं को कैसे अधिक सक्षम बनाया जाए। वाय-20 के विविध प्रकार के आयोजन उसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

उदघाटन सत्र में जी-20 यूथ के प्रमुख व स्टूडो मैट्रिक्स के फलित सिजारिया ने वाय-20 के उद्देश्यों से सभी को अवगत कराया। उन्होंने कहा कि भारत के पास आने वाले समय में सर्वाधिक युवाओं की तादाद होगी। ऐसे में सक्षम युवा ही समर्थ भारत का निर्माण करेंगे। इस अवसर पर अकलतरा के बायो डाइवर्सिटी विशेषज्ञ अनुपम सिसोदिया ने भी अपने विचार प्रस्तुत किए। इस अवसर पर आरती सिंह, नपा अध्यक्ष शांति भारती, अशोक अग्रवाल, ईश्वर खंडेलिया, आरके विश्वकर्मा, परंजय सिंह, वर्षा यादव, चंद्रिका नायक, गायत्री यादव, पुष्पेंद्र पुरी गोस्वामी, पुष्पेंद्र कुमार साहू, अरसा नायडू, अरूणा शर्मा, अभिषेक प्रधान समेत अन्य गणमान्य उपस्थित रहे।

रूस-भारत छात्रवृत्ति का लें लाभ : आंद्रे नेवेस्की

उदघाटन सत्र को रूस से आए विश्व युवा संगठन के सदस्य आंद्रे नेवेस्की ने संबोधित किया। उन्होंने अपने अनुभवों को साझा करते हुए बताया कि कैसे रूस के छोटे से गांव से होते हुए उन्होंने अपने पसंदीदा विषय में विशेषज्ञता हासिल की। आंद्रे ने उपस्थित प्रतिभागियों से रूस और भारत के मध्य चलाए जाने वाले विविध प्रकार की छात्रवृत्ति योजनाओं के लाभ लेने की अपील की। उन्होंने सभी के उज्ज्वल भविष्य व मजबूत भारत की कामना की। अपने अनोखे अंदाज में रूसी व हिंदी में नमस्ते बोलकर उन्होंने सभी को प्रभावित किया। वॉय-20 के पहले दिन प्रधानमंत्री युवा लेखक के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान बना चुके तथा कैंब्रिज व ब्रिस्टिल विश्वविद्यालय के विद्यार्थी रहे सौहार्द डी., युवा राजदूत के रूप में चर्चित राधिका भारद्वाज, किंग्स कॉलेज की अनिका जोशी, जी-20 यूथ के प्रमुख फलित सिजारिया, ऋषि गुप्ता, खुशी चड्ढा, ने विभिन्न सत्रों के माध्यम से युवाओं को टिप्स दिए।

18 संस्थानों के 600 प्रतिभागी ले रहे भाग

वॉय-20 के कार्यक्रम में अकलतरा क्षेत्र के 18 शिक्षण संस्थान, कन्या उ.मा. शाला अकलतरा, आरके सिंह शाला, ऋषभ विद्योदय महाविद्यालय बनाहिल, अघोर विद्यापीठ, शासकीय शाला अमोरा, आईटीआई अकलतरा, न्यू बोको पब्लिक स्कूल, सरस्वती शिशु मंदिर, महावीर बाल संस्कार केंद्र, लायंस डीएवी पब्लिक स्कूल, स्वामी आत्मानंद, सरस्वती शिशु मंदिर बलौदा, स्वामी विवेकानंद स्कूल बलौदा, लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज बलौदा, कन्याशाला बलौदा, स्वामी आत्मानंद स्कूल बलौदा के 600 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। वॉय-20 के दूसरे दिन यानि 15 जुलाई को सुप्रसिद्ध पत्रकार अशोक श्रीवास्तव मुख्य अतिथि रहेंगे। वहीं उच्च शिक्षा में संभावनाएं, दुनिया के विश्वविद्यालयों में नामांकन की प्रक्रिया, प्रतिभागियों के स्वयं से प्रतिबद्धता आदि विषयों पर व्याख्यान का आयोजन किया जाएगा। समापन समारोह में अपने अनुभवों को समेटते हुए प्रतिभागी बेहतर भारत के निर्माण में अपने योगदान के संकल्पों के साथ विदा होंगे।

जन्मदिन पर दीपक बैज को मिला सोनिया- राहुल का आशीर्वाद

नई दिल्ली/ जगदलपुर। बस्तर सांसद एवं छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त अध्यक्ष दीपक बैज ने आज कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष यूपीए चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी तथा पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी से उनके दिल्ली स्थित आवास में भेंट कर छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस संगठन की जिम्मेदारी सौंपे जाने पर कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए उनका आशीर्वाद प्राप्त किया।

छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सांसद दीपक बैज ने श्रीमती गांधी तथा राहुल गांधी को विश्वास दिलाया कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में आगामी विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक सफ्लता का क्रम दोहराते हुए छत्तीसगढ़ राज्य में कांग्रेस की गौरवशाली विजय यात्रा को जारी रखेगा। इस संकल्प के साथ छत्तीसगढ़ कांग्रेस के सभी नेता और कार्यकर्ता समस्त राष्ट्रीय नेताओं, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मार्गदर्शन में कांग्रेस संगठन को और अधिक मजबूत बनाने प्रतिबद्ध हैं।

विदित है कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष सांसद दीपक बैज ने गुरुवार को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे एवं संगठन महासचिव श्री वेणुगोपाल से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद एवं मार्गदर्शन प्राप्त किया था। आज शुक्रवार को श्री बैज ने कांग्रेस की सर्वोच्च नेता सोनिया गांधी तथा राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी से मुलाकात कर उनका मार्गदर्शन एवं आशीर्वाद प्राप्त किया।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सांसद दीपक बैज को छत्तीसगढ़ कांग्रेस की कमान सौंपे जाने पर पहले ही प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कह चुके हैं कि दीपक बैज युवा नेता हैं और उन्हें छत्तीसगढ़ कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए जाने से युवाओं सहित सभी वर्गों में उत्साह है।पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने भी दीपक बैज को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि दीपक बैज छत्तीसगढ़ कांग्रेस को और अधिक ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए पार्टी के वरिष्ठ जनों के मार्गदर्शन एवं सहयोग से ऐसे प्रयास करेंगे, जो उनसे अपेक्षित हैं।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और विशेष तौर पर सोनिया गांधी तथा राहुल गांधी से आमतौर पर इतनी जल्द मुलाकात का समय नहीं मिल पाता है क्योंकि यह नेता बहुत व्यस्त हैं। इन्हें पूरे देश के पार्टी मामले देखना होते हैं लेकिन छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष युवा सांसद दीपक बैज को पार्टी के सभी नेताओं का सहज आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। संसद में सांसद दीपक बैज के उत्कृष्ट प्रदर्शन से पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व पहले से ही परिचित है और संसद में उनके जोशीले भाषण से, उनके द्वारा छत्तीसगढ़ के लिए उठाए गए मुद्दों से प्रभावित कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उन्हें प्रोत्साहित करते रहे हैं तथा राहुल गांधी का मार्गदर्शन उन्हें मिलता रहा है।

प्रियंका गांधी से मिले छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रमुख दीपक बैज

नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रमुख सांसद दीपक बैज ने शुक्रवार को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा से दिल्ली स्थित निवास में मुलाकात कर उनसे मार्गदर्शन एवं आशीर्वाद प्राप्त किया। श्रीमती प्रियंका गांधी ने श्री बैज को उनके जन्मदिन की बधाई देते हुए नवीन जिम्मेदारी के लिए बधाई व शुभकामनाएं दीं।

कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने श्री बैज को छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए विश्वास व्यक्त किया कि इससे युवाओं को प्रोत्साहन मिलेगा। कांग्रेस हमेशा वरिष्ठ नेताओं के अनुभव को अहमियत देते हुए युवा नेतृत्व को प्रोत्साहित करती है। कांग्रेस संगठन पीढ़ियों का संगम है।

एकल उपयोग प्लास्टिक के विलोपन के लिए गठित टास्क फोर्स की बैठक सम्पन्न

रायपुर। मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन की अध्यक्षता में एकल उपयोग प्लास्टिक के विलोपन हेतु गठित टास्क फोर्स की तीसरी बैठक आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में सम्पन्न हुई। मुख्य सचिव ने एकल उपयोग प्लास्टिक के विलोपन हेतु व्यापक कार्ययोजना के तहत प्रभावी क्रियान्वयन करने के निर्देश अधिकारियों को दिए है। उन्होंने एकल उपयोग प्लास्टिक के विकल्प के रूप में बर्तन बैंक, कपड़े, कागज की थैली और दोना-पत्तल के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक कार्य करने कहा है। बैठक में मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू मौजूद थे।एकल प्लास्टिक के विलोपन हेतु व्यापक प्रचार प्रसार एवं जन-जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है। बैठक में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक के विलोपन के लिए की जा रही विभिन्न गतिविधियों के बारे में प्रस्तुतिकरण के जरिए विस्तृत जानकारी दी गई। आवास एवं पर्यावरण विभाग के अधिकारियों को शासकीय कार्यालयों को एकल प्लास्टिक से मुक्त करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश तैयार कर सामान्य प्रशासन विभाग से समन्वय कर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। इसी तरह से उन्होंने स्कूल और कॉलेजों में आयोजित होने वाले विज्ञान प्रदर्शनियों में सिंगल यूज प्लास्टिक के विलोपन के संबंध में प्रादर्श बनाने छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने कहा है। सभी जिलों के कलेक्टर एकल उपयोग प्लास्टिक प्रतिबंध के लिए जिले में कार्ययोजना बनाएं और इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए नगरीय निकायों एवं पंचायतों से आवश्यक समन्वय कर उनसे सहयोग लें। एयरपोर्ट, रेल्वे स्टेशन, औद्योगिक क्षेत्र एवं सार्वजनिक उपक्रमों सहित अन्य संस्थाओं के अधिकारियों को भी एकल उपयोग प्लास्टिक प्रतिबंध के लिए आवश्यक कार्यवाही करने कहा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित इस बैठक में नगरीय प्रशासन विभाग के विशेष सचिव अयाज तम्बोली सहित आवास एवं पर्यावरण, वाणिज्य एवं उद्योग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, नगरीय प्रशासन, छत्तीसगढ़ पर्यावरण मण्डल सहित छत्तीसगढ़ काउंसिल ऑफ साइंस एण्ड टेक्नालॉजी के अधिकारी शामिल हुए।

कार्यस्थलों पर होने वाली यौन हिंसा पर त्वरित कार्यवाही करें : संतोष शर्मा

रायपुर। उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील क्रमांक 2482/2014 ऑरलियानों फर्नाडीज वि0 गोवा राज्य व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 12.05.2023 में दिये निर्देशों के परिपालन में दिनांक 14.07.2023 को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर वैकल्पिक विवाद समाधान केन्द्र में कार्यस्थलों पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न अधिनिमय 2013 पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसकी अध्यक्षता संतोष शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायपर द्वारा की गई। उक्त कार्यक्रम में व्याख्यान लवकेश प्रताप सिंह बघेल, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीशरायपुर द्वारा दिया गया। जिनके द्वारा अपने वक्तव्य में बताया गया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 एवं 15 में समानता और अनुच्छेद 21 में प्राण एवं गरिमा से जीवन व्यती करने के मूलभूत अधिकारों एवं मुक्त सुरक्षित वातावरण के अधिकार की बात कही गई है। महिलाओं की सुरक्षा के लिये समय समय पर विभिन्न कानून बनाये गये। इसके बावजूद भी महिलाओं की सुरक्षा की कमी को दृष्टिगत रखते हुये घरेलु हिंसा अधिनियम, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 बनाये गये, जिसमें अपराधी को दंडित किये जाने की व्यवस्था की गई किंतु समय की गतिशीलता के साथ यह महसूस किया जाने लगा कि महिलाएं घर से निकलकर अपने कार्यक्षेत्र पर जाने लगी है और कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ उत्पीड़न की अनेक घटनाएं होती रही है, जिसके संबंध में कोई स्पष्ट कानून नहीं बना था और इस कमी को उच्चतम न्यायालय ने विशाखा वि0 स्टेट ऑफ राजस्थान वर्ष 1997 में महसूस किया और कार्यस्थल पर महिलाओं के उत्पीडन की रोकथाम के लिये विभिन्न दिशा-निर्देश जारी किये और उसी दिशा निर्देश के परिप्रेक्ष्य में कानून की दृष्टिगत रखते हुये वर्ष 2013 में केन्द्र सरकार ने कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 पारित किया जो 9 दिसंबर 2013 को प्रभाव में आया। जिसके अंतर्गत 1- किसी स्त्री को उसकी इच्छा के खिलाफछूना या छूने की कोशिश करना 2- अनुचित लाभ देकर यौन संबंध बनाने की मांग करना 3 अश्लील बातें करना 4 अश्लील तस्वीरें वीडियो दिखाना या भेजना 5-अन्य यौन कार्य जो बातचीत लिखकर या छूकर किये गये हो।

आवारा पशुओं पर कई सालों से कानून पर लागू नहीं : हाईकोर्ट

■ **सीएस की अध्यक्षता में समिति बनाने के निर्देश**

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ की सड़कों पर आवारा पशुओं के घूमने को लेकर हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। कहा कि कई सालों से कानून बने हैं, लेकिन उन्हें अब तक लागू नहीं किया गया है। कोर्ट ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति बनाने का निर्देश दिया है। इस समिति में केंद्र और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अफसर भी शामिल रहेंगे। सड़कों पर आवारा पशुओं के विचरण से लगातार हो रहे हादसों को लेकर दायर जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई।

एनएचएआई के वकील धीरज वानखेड़े ने राजमार्ग संबंधी कई रूल्स और एक्ट डिवीजन बेंच में प्रस्तुत किए और बताया कि कई सालों से यह बने हुए हैं। इस पर कोर्ट ने कहा कि, इन कानूनों को अब तक लागू नहीं किया गया है। राज्य शासन के वकील ने हाईकोर्ट के पूछने पर बताया कि आवारा मवेशियों को नगर निगम पकड़ रहा है। कोर्ट ने कहा कि पीआईएल लगाने के बाद आप लोग यह सब कर रहे हैं। इसके बाद कोर्ट ने मुख्य सचिव और डायरेक्टर एनएचएआई से विमर्श कर कमेटी बनाने के निर्देश दिए।

कोर्ट ने समिति के तहत क्या काम किए जाएंगे, कौन कौन क्या जवाबदारी लेंगे, यह सब विस्तार से रिपोर्ट में बताने के निर्देश दिए हैं। यह कमेटी इस समस्या के समाधान के लिए कार्रवाई करने के बाद इस संबंध में एक सप्ताह में रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इस रिपोर्ट पर चार सितंबर को मामले की अगली सुनवाई की जाएगी। राजेश चिकारा व संजय रजक की जनहित याचिका पर कोर्ट में सुनवाई चल रही है। इसमे मुख्य मार्गों और शहर की सड़कों पर पशुओं को खुला छोड़ने से हो रही दुर्घटनाओं की जानकारी देते हुए कार्रवाई की मांग की गई है।

अतिसंवेदनशील क्षेत्र चांदामेटा में बच्चों को मिला अपना नया स्कूल भवन

उमंगों से खिल उठे बच्चों के चेहरे जब अपने ही हाथों किया स्कूल भवन का उद्धाटन

रायपुर। बस्तर जिले के अतिसंवेदनशील क्षेत्र चांदामेटा प्राथमिक शाला को पहली बार स्वयं का स्कूल भवन मिला है। प्रशासन ने इस अतिसंवेदनशील क्षेत्र में संवेदनशील पहल करते हुए नए स्कूल भवन का उद्धाटन स्कूली विद्यार्थियों के हाथों कराया। अपने ही हाथों अपने नए स्कूल भवन का लोकार्पण करते वक्त बच्चों के चेहरे उमंग से खिल उठे थे। ऐसा लग रहा था मानों यहां बच्चे विशिष्ट अतिथि हैं और उपस्थित अधिकारी और ग्रामीण सभी उनका हौसला बढ़ा रहे हों।

नक्सल हिंसा से कभी प्रभावित रहा चांदामेटा आज शिक्षा और सामाजिक स्तर पर आगे बढ़ रहा है। सरकार की पहल से यहां न केवल स्कूल नियमित रूप से चलाया जा रहा बल्कि पढ़ाई के लिए बच्चे भी दुर्गम क्षेत्रों से यहां आ रहे हैं। चांदामेटा में स्कूल भवन के लिए जमीन किसान श्री आयता मरकाम ने अपनी जमीन दान में दी है ताकि बच्चों को गांव में ही बेहतर शिक्षा के अनुकूल माहौल मिल सकें। स्कूल के उद्घाटन कार्यक्रम में अधिकारियों एवं ग्रामीणों ने श्री आयता को स्कूल भवन के लिए जमीन दान में देने के लिए धन्यवाद दिया और पुष्पगुच्छ देकर उनका सम्मान किया। एक ऐसा समय भी था जब इस इलाके में स्कूल संचालित कर पाना असंभव था। निजी भवनों में बड़ी कठिनाईयों के बीच स्कूल संचालित होते थे। लेकिन अब प्रशासन ने नया स्कूल भवन तैयार किया है, जिसमें नियमित रूप से कक्षाएं लग रही है। खुशी की बात है कि गांव के बच्चों ने ही अपने लिए तैयार स्कूल का शुभारंभ किया।

गौरतलब है कि प्रदेश के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पिछले चार सालों में अनेकों विकास कार्य किए गए हैं, जिससे प्रदेश के सुदूर वनांचल के इलाके मुख्यधारा से जुड़कर प्रदेश के विकास में अपने भागीदारी दे रहे हैं। इनमें ऐसे इलाके भी शामिल है, जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के कारण मूलभूत सुविधाओं से वंचित थे। शिक्षा के लिए स्कूलों का संचालन का नहीं हो पा रहा था। संवेदनशील प्रदेश सरकार ने बस्तर संभाग में नक्सली गतिविधियों के कारण बंद पड़े 314 स्कूलों को न केवल पुनः प्रारंभ किया बल्कि विकास, विश्वास, और सुरक्षा के अपने संकल्प को मजबूती के साथ स्थापित किया। जिला प्रशासन के अधिकारियों ने बताया कि चांदामेटा के बच्चे अब अपना भविष्य गढ़ सकेंगे। भवन को सहेजने-संवारने की जिम्मेदारी ग्रामीणों ने ली है और यह बड़े बदलाव का सुखद संदेश है। भवन को बनाने में सुरक्षा बल के जवानों ने बहुत मेहनत की है। जिला प्रशासन के अधिकारियों ने बताया कि ग्रामीणों की मांग पर प्रशासन द्वारा चांदामेटा के लिए सड़क, स्कूल, आंगनबाड़ी की सुविधाएं दी गई है और आगे भी विकास की अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी। इससे पहले कैंप में स्कूल संचालित की जा रही थी अब भवन बनने से बच्चों को सुविधा होगी।

बेबसी का इक समंदर दूर तक फैला हुआ.....

आरएसएस और भाजपा का एक धड़ा शुरू से समान नागरिक संहिता की वकालत करता रहा है। यह मुद्दा भाजपा के एजेंडे में शामिल है। प्रथम दृष्टया यह कानून बड़ा लुभावना भी लगता है। इसके पीछे का तर्क यह है कि देश के सभी नागरिकों पर सामान कानून लागू होना चाहिये,सतही तौर पर उचित भी लगता है लेकिन इस बात का विरोध क्यों किया जा रहा है...? आपका सीधा जवाब होगा कि इससे चूंकि अल्पसंख्यक वर्ग प्रभावित होगा इसलिये...!

लेकिन इस कानून से सिर्फ अल्पसंख्यक ही नहीं बल्कि एक बड़ा समुदाय भी प्रभावित होने वाला है,समान नागरिक संहिता की बात करनेवालों की नजर सिर्फ अल्पसंख्यकों के अधिकारों को हड़पने भर का नहीं बल्कि संसाधनों से भरी जमीन पर भी अपनाअधिकार हासिल करना है। हमारा संविधान लोगों को अपनी धारणा,आस्था और परंपरा के साथ रहने और जीने की आजादी देता है। यदि आप किसी धर्म को मानते हैं तो उसके अनुसार आचरण करें,उसकी परंपराओं का निर्वहन करें। लेकिन जब भी समान नागरिक संहिता की बात होती है तो कहा जाता है कि इससे सिर्फ मुसलमान प्रभावित होगा। वह चार शादियां नहीं कर सकता,वह आसानी से तलाक नहीं ले सकता वगैरह-वगैरह...। कुल मिलाकर यह कानून सिर्फ मुसलमानों के लिए ही मुसीबत साबित होगा..लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। समान नागरिक संहिता जब लागू होगी तो देश का मूल निवासी यानी आदिवासी भी इसके जद में आएगा। देश के कई जनजातीय समुदायों में भी अलग -अलग परंपराएं और मान्यताएं हैं,उन्हें भी इस संविधान के तहत उनकी मान्यताओं के अनुरूप रहने,व्यवहार करने,विवाह करने की स्वतंत्रता है...? उनके लिए भी उनके अधिकारों को सुरक्षित रखने अलग से कानून हैं ? इसमें सबसे महत्वपूर्ण है धारा170 ख,जिसके तहत आदिवासी विकास खंडों में उनकी जमीन कोई गैर आदिवासी नहीं खरीद सकता,सामान्य विकास खंडों में उनकी जमीन सामान्य आदमी बिना कलेक्टर की अनुमति के नहीं खरीद सकता। इस नियम पर कई बार उद्योगपतियों ने उंगली उठाई है क्योंकि इसके कारण आदिवासी इलाकों में संसाधनों का दोहन या उद्योगों की स्थापना में कई रोड़े आते हैं।ओडिशा के नियमगिरि में वेदांता कंपनी की आयरन ओर माइंस इसी कारण रद्द कर दी गई थी।जब यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा तब 170 ख जैसे नियमों को हटाया जा सकेगा... उद्योगपतियों को मुक्त हस्त से आदिवासियोंऔर उनके क्षेत्र के संसाधनों को लूटने का अवसर मिलेगा। जब सबके लिए एक कानून होगा तब आरक्षण की व्यवस्था भी बेमानी हो जायेगी क्योंकि सबके लिए एक कानून में यह व्यवस्था भी फिट नहीं बैठती है।इस तरह की मांग भाजपा के अंदरखाने से उठने लगी है।इसके अलावा यदि सबके लिए एक कानून होगा तो अनुसूचित जाति/जनजाति अधिनियम,जिससे इस तबके की सुरक्षा का बड़ा बेहतर कानून माना जाता है उसकी उपयोगिता और प्रासंगिकता क्या होगी...! संभवतः तुरंत इन सभी कानूनों पर कोई निर्णय न हो पाए लेकिन कालांतर में ये सभी कानूनअसंवैधानिक हो जाएंगे और कोर्ट के जरिये या अमेंडमेंट के जरिये ही इन्हें खत्म किया जाता रहेगा। क्या इस कानून के पारित होने के बाद सिक्ख कृपाण लेकर कहीं जा पाएंगे? अलग अलग धर्मों में अपनी अलग परंपराएं, मान्यताएं, धारणाएं हैं। मुस्लिम और ईसाई धर्म में विवाह एक समझौता हैऔर हिंदू धर्म के लिए यह जन्म जन्मांतर का रिश्ता...। इस यूनिफॉर्म सिविल कोड में विवाह को क्या माना जाएगा ?जन्म जन्मांतर का रिश्ता या एक समझौता ? और कोई यह कैसे तय करेगा कि हम अपने विवाह संस्कार को समझौता समझें या जन्म जन्मांतर का रिश्ता। यह तो हमें तय करना है। हिंदू विवाह अधिनियम में तलाक की प्रक्रिया काफ़ी कठिन है,मुस्लिमों में आसान,ऐसे में यूनिफॉर्म सिविल कोड इस प्रक्रिया को आसान करेगा या सरल ? कई आदिवासी समुदायों को भी एक से अधिक विवाह करने की छूट है,उनके साथ क्या सलूक किया जाएगा ? ऐसे कई ज्वलंत सवाल हैं।अव्वल यही माना जा रहा है कि सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड आदिवासियों के हितों,उनकी परपराओं, उनकी जमीनों के अधिकार को सबसे पहले संकुचित करेगी और धीरे - धीरे उन्हें इससे वंचित होना पड़ेगा। क्योंकि मुस्लिमों की परंपराओं,ईसाइयों की आस्था से किसी को नुकसान नहीं है लेकिन आदिवासियों के अधिकारों से उद्योगपति सबसे ज्यादा परेशान हैं और उन्हीं के परंपराएं, मान्यताएं और उनके अधिकारों को कम करने या खत्म करने सरकार या यूं कहें उद्योगपतियों के पक्षकार इस कानून के साथ हैं और उससे ही उन्हें फायदा होने वाला है।

भूपेश ने ले ली है विस चुनाव को लेकर टोह....

छ्ग के सीएम भूपेश बघेल ने सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा पूरा कर लिया है। सभी विधानसभा क्षेत्रों में वे जहां आम लोगों से संवाद करते रहे,अपनी सरकार की योजनाओं के बारे में पूछताछ भी किया वहीं लोगों की समस्याओँ का मौक़े में ही निराकरण का प्रयास किया,कई विकास कार्यों की घोषणा की साथ ही वर्तमान विशेषकर कांग्रेस के विधायकों की टोह भी लेते रहे,उनके कार्यकलापों की जानकारी ली साथ ही आगामी विस चुनाव में उनके जीतने की सम्भावनाओं पर भी एक नजर डालने का प्रयास किया,उनके सामने अगले विस चुनाव को लेकर प्रत्याशी को लेकर नजरिया भी एक तरह से साफ हो गया है यही नहीं कॉंग्रेस के घोषणापत्र के बारे में भी ब्लुप्रिंट तैयार भी हो गया है। अब वे युवाओं से सीधे मुख़ातिब होने की तैयारी में हैं।

भाजपा का सर्वे, अधिकतम 34 सीटें.....?

भाजपा के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह के सर्वे के मुताबिक आज की स्थिति में छ्ग में आगामी विधानसभा चुनाव में 34 सीटों पर भाजपा की जीत तय है तो 14 सीटों पर भाजपा जीत के करीब है?ऐसे हालात में भाजपा अपने सांसद विजय बघेल, अरुण साव,सुनील सोनी, रेणुका सिंह,गुहाराम अजगले आदि को विधानसभा प्रत्याशी बना सकती है वहीं विधायक डॉ रमनसिंह, बृजमोहन अग्रवाल, धरम लाल कौशिक को लोकसभा प्रत्याशी बना दे तो आश्चर्य नहीं है?इधर सत्ताधारी दल कांग्रेस 75+अपना लक्ष्य तय करके चल रही है,अभी 72 विधायक कांग्रेस के हैं।भाजपा के उच्च पदस्थ सूत्रों की मानें तो शाह के सर्वे में बस्तर संभाग से 4 विधानसभा पर जीत की उम्मीद है। सरगुजा संभाग के सिंहदेव फैक्टर के बावजूद उम्मीद की जा रही है कि यहां से 6 सीट पर पार्टी के उम्मीदवार की जीत हो सकती है। भूपेश सरकार में मंत्री टीएस सिंहदेव को कुछ दिन पहले ही डिप्टी सीएम बनाया गया है।भाजपा की मानें तो कांग्रेस के इस उपाय का असर सरगुजा में नहीं दिखेगा। दुर्ग संभाग की 8,रायपुर संभाग की 7 और बिलासपुर संभाग की 9 सीट पर पार्टी उम्मीदवार की जीत की उम्मीद की जा रही है।वर्तमान में सरगुजा और बस्तर संभाग की एक भी सीट पर भाजपा के विधायक नहीं हैं। इधर आठ विधायकों का टिकट कटना तय माना जा रहा है।इधर 5 सांसदों को विस चुनाव मैदान में उतारने पर विचार किया गया है।वैसे सवाल यह है कि कॉंग्रेस कितने विधायकों की टिकट काट रही है क्योंकि कांग्रेस आलाकमान को खबर मिली है कि कुछ विधायक पिछली बार कांग्रेस की लहरऔर 15 सालों की भाजपा सरकार से नाराजगी के चलते जीत गये थे....?

दीपक कांग्रेस अध्यक्ष,मरकाम बने सरकार के मंत्री

प्रदेश के विधानसभा चुनाव से लगभग 100 दिन पहले कांग्रेस ने बड़ा बदलाव करते हुए मोहन मरकाम की जगह बस्तर सांसद दीपक बैज को नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। पिछले तीन महीने से बैज को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की कवायद चल रही थी। बैज अब तक के सबसे युवा प्रदेश अध्यक्ष बने हैं।चित्रकोट विधानसभा क्षेत्र से दो बार विधायक और बस्तर लोकसभा क्षेत्र के सांसद बैज गिनती कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के करीबी नेताओं में होती है। प्रदेश अध्यक्ष के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की भी पहली पसंद बैज ही थे।दीपक बैज वर्ष 2008 में एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष के रूप में अपनी राजनीतिक पारी शुरू की। 15 साल में वह प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी तक पहुंच गए। 14 जुलाई 1981 को बस्तर के गढिया में जन्में बैज 2009 में युवक कांग्रेस के बस्तर जिला महासचिव बने।वर्ष 2013 में कांग्रेस पार्टी ने पहली बार उन्हें विधानसभा का टिकट दिया और जीत मिली। 2018 का चुनाव जीतकर वह एक बार फिर विधानसभा पहुंचे। प्रदेश में सरकार बनने के बाद 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में बैज को बस्तर लोकसभा का टिकट मिला और उन्होंने बस्तर लोकसभा सीट पर कांग्रेस के 25 वर्ष के वनवास को दूर करते हुए जीत दर्ज की।इधर मोहन मरकाम को भूपेश मंत्रिमंडल का हिस्सा बनाया गया है वहीं मंत्रिमंडल से प्रेमसिंह टेकाम को हटा दिया गया है।उन्हें योजना आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है, उन्हें कबीना मंत्री का दर्जा प्राप्त है।

कुछ मंत्रियों के विभाग भी बदले गये....

मोहन मरकाम को नया मंत्री बनाने के साथ ही कुछ मंत्रियों के विभाग भी बदले गये हैं। उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव को स्वास्थ के साथ ऊर्जा,ताम्रध्वज साहू को गृह, जेल के साथ ही कृषि, पशु, मछली पालन, रविन्द्र चौबे से कृषि लेकर शालेय शिक्षा, सहकारिता और नये मंत्री मोहन मरकाम को अजा/ज जा के साथ अल्पसंख्यक विभाग की जिम्मेदारी दी गई है।रविंद्र चौबे तबियत ख़राब होने के कारण स्वयं कृषि विभाग छोड़ना चाहते थे।

आपरेशन मुस्कान में जांजगीर जिला प्रथम...

छ्ग में गुमशुदा बच्चों की पतासाजी के लिये आपरेशन मुस्कान के तहत 1 जून से 30जून तक पुलिस विभाग द्वारा चलाये गये अभियान के तहत 559 गुमशुदा बच्चों को बरामद करने में सफलता मिली है।जिसमे जांजगीर चांपा (एसपी विजय अग्रवाल) से सर्वाधिक 76 बच्चों को बरामद करके छ्ग में पहले स्थान पर रहा वहीं रायपुर (एसपी प्रशांत अग्रवाल) बिलासपुर (एसपी संतोष सिंह) और सक्ति जिले (एसपी अहिरे) से क्रमशः 56,52 तथा 52 बच्चे बरामद किये गये हैँ। अभियान में उप्र,मप्र,कश्मीर तेलंगाना, महाराष्ट्र,पंजाब, दिल्ली,राजस्थान,हरियाणा ओर कर्नाटक राज्यों से बच्चे बरामद किये गये?अपनी कार्यप्रणाली के चलते जांजगीर एसपी विजय अग्रवाल को आपरेशन मुस्कान में अच्छी सफलता के लिये डीजीपी अशोक जुनेजा ने प्रशंसा पत्र भी दिया है ऐसा पता चला है।

ओर अब बस....

- ईडी ने छ्ग के कुछ आईपीएस अफसरों की जमीन,फ्लेट, ट्रांसपोर्ट की जानकारी एकत्रित कर रही है....
- दुर्ग से महादेव एप्स से सट्टा संचालित करने वाले 2 प्रमुख लोगों के खिलाफ आउट लुक नोटिस जारी किया गया है...?
- एडीशनल एसपी की तबादला सूची में 2 चर्चित अफसरों का नाम नहीं होना चर्चा में है..?

छत्तीसगढ़/राजधानी
प्रमुख समाचार

कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज आज पदभार ग्रहण करेंगे

रायपुर। नव-नियुक्त प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं सांसद दीपक बैज 15 जुलाई 2023 को दोपहर 1.45 बजे रायपुर विमानतल पहुंचेंगे एवं दोपहर 03 बजे प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन, रायपुर में पदभार ग्रहण करेंगे। पदभार ग्रहण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, मंत्री एवं निवृत्तमान प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम, विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के संयुक्त सचिव एवं सह-प्रभारी विजय जांगिड़ सहित मंत्रीमंडल के सदस्यगण व वरिष्ठ नेतागण एवं कांग्रेसजन उपस्थित रहेंगे।नव नियुक्त प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का स्वागत माना विमानतल से राजीव भवन तक कांग्रेसजनों द्वारा भव्य स्वागत किया जायेगा। कांग्रेस के द्वारा अपने नव नियुक्त अध्यक्ष के स्वागत को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी की गयी है। इस हेतु अलग-अलग नेताओं को अलग प्वांईट की जवाबदारी दी गयी। जैनम चौक पर प्रदेश युवा कांग्रेस आकाश शर्मा। व्हीआईपी टर्निंग में एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष नीरज पाण्डेय।

भ्रष्टाचार पर प्रेस कांफ्रेंस कर तथ्यहीन आरोप : शुक्ला

रायपुर। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल की पत्रकार वार्ता का जवाब देते हुये प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा के खून में भ्रष्टाचार है। 15 सालों तक प्रदेश को लूटने वाले भाजपाईयों को सोते जागते भ्रष्टाचार ही दिखता है। बड़ा हास्यास्पद लगता है कि मंत्री रहते हुये डॉलर में घूस लेने वाले तथा जलकी में किसानों और सरकारी जमीन कब्जा कर फार्म हाउस बनाने वाले बृजमोहन अग्रवाल भ्रष्टाचार पर प्रेस कांफ्रेंस कर कांग्रेस पर तथ्यहीन आरोप लगा रहे है। रमन सरकार के 1 लाख करोड़ के भ्रष्टाचार पर बृजमोहन की बोलती क्यों बंद है? 36000 करोड़ का नान घोटाला, 4400 करोड़ के शराब घोटाला, 6000 करोड़ के चिटफंड घोटाले पनामा पेपर वाले अभिषेक सिंह, 1677 करोड़ का गौशाला घोटाले पर, इंदिरा प्रियदर्शिनी बैंक घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह सहित बृजमोहन अग्रवाल को भी घूस देने की स्वीकारोक्ति प्रमुख आरोपी ने अपने नार्को टेस्ट में किया है। भाजपा के 15 सालों में 34 घोटाले हुये थे जो प्रदेश की जनता के जुबान पर है इनकी जांच कराने की बात आती है।

बेरोजगारों के लिए जॉब फेयर का आयोजन 18 को

रायपुर। जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र द्वारा 18 जुलाई को जॉब फेयर का आयोजन किया जा रहा है। यह जिला रोजगार कार्यालय पुराना पुलिस मुख्यालाय में प्रातः 11 बजे से 2 बजे तक आयोजित होगा। इस प्लेसमेंट कैम्प का उद्देश्य छत्तीसगढ़ के स्थानीय शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना है। जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र के उपसंचालक ने बताया कि इस कैम्प के माध्यम से VaiManika Aerospace, Universal Agrico Forestry Pvt.Ltd. Raipur °ß´ Shefali Business International द्वारा भर्ती की जाएगी। कैम्प में 10वीं से स्नातक, (एग्रीकल्चर/विज्ञान) आई.टी.आई. कोपा उत्तीर्ण शैक्षणिक योग्यता वाले अभ्यार्थियों की भर्ती होगी। विभिन्न संस्थाओं द्वारा भर्ती किए जाने वाले पदों में ड्रोन पायलट, डिस्ट्रिक मैनेजर, डाटाइंटी ऑपरेटर, फिल्ड सुपरवाइजर और फिल्ड सेल्स एक्सीक्यूटिव इत्यादि 147 से अधिक पद शामिल है। विभिन्न अनुभव के आधार पर होने वाले पदों का वेतन 10 हजार से 20 हजार प्रतिमाह होगा।

सत्तर वर्ष के भूतपूर्व सैनिकों को मिलेगी सम्मान निधि

रायपुर। रायपुर संभाग के 70 वर्ष से अधिक आयु के भूतपूर्व सैनिकों को सम्मान निधि दी जाएगी। इसके लिए उन्हें जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में आवेदन करना होगा। आवेदन के साथ वांछनीय दस्तावेजों को सैनिक बोर्ड भेजा जाएगा। सैनिक बोर्ड में दस्तावेजों के परीक्षण के बाद सम्मान निधि की स्वीकृति दी जाएगी और राशि भूतपूर्व सैनिकों के खाते में सीधे जमा होगी। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी ने आज यहां बताया कि रायपुर संभाग के धमतरी, रायपुर, बलौदाबाजार-भाटापारा, महासमुन्द और गरियाबंद जिले के 70 वर्ष, 75 वर्ष, 80 वर्ष, 85 वर्ष, 90 वर्ष, 100 वर्ष या उससे अधिक आयु पूर्ण कर चुके भूतपूर्व सैनिकों को सम्मान निधि की पात्रता हैं। ऐसी सभी पात्र भूतपूर्व सैनिक अपनी सेवा पुस्तिका प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, आधार कार्ड की प्रति, बैंक पास बुक की प्रति एवं निवास प्रमाण पत्र के साथ जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। दस्तावेजों का परीक्षण कर सही पाए गए आवेदनों को संचालनालय सैनिक बोर्ड को अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा। सैनिक बोर्ड से अनुमोदन के बाद पात्र भूतपूर्व सैनिकों को निर्धारित सम्मान निधि दी जाएगी।

अपने भ्रष्टाचार को ढँकने की कुचेष्टा कर रहे हैं सीएमः चौधरी

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री ओ.पी. चौधरी ने कहा है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 'छत्तीसगढ़ियावाद के नाम पर अपने भ्रष्टाचार को ढँकने की कुचेष्टा कर रहे हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ बर्बाद' कर उसे छत्तीसगढ़ियावाद' का चोंगा पहनाने का घिनौना प्रयास मुख्यमंत्री बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस ने किया है। श्री चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री बघेल दरअसल अपने काले कारनामों को ढँकने के लिये छत्तीसगढ़ियावाद' का उपयोग कर रहे हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि छत्तीसगढ़ियावाद कहते किसे हैं? भूपेश-सरकार ने बीते 5 सालों में जो किया है, उसको छत्तीसगढ़ियावाद नहीं, छत्तीसगढ़ बर्बाद' कहते हैं। भाजपा प्रदेश महामंत्री श्री चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री बघेल छत्तीसगढ़ियावाद के नाम पर ढोंग करते हैं। यह छत्तीसगढ़ियावाद नहीं, छत्तीसगढ़ बर्बाद करने का अभियान है। अपने माफिया राज, भ्रष्टाचार में कांग्रेस सरकार आकंठ डूब गई है।

कर्मचारियों की मांग को भाजपा के घोषणा पत्र में शामिल करेंगे : साव

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने ऐलान किया है कि भाजपा संविदा,अनियमित,दैनिक वेतन भोगी व अन्य प्रकार के अस्थाई कर्मचारियों की मांग को अपने घोषणा पत्र में शामिल करेगी और सरकार बनते ही भाजपा अपना वादा पूरा करेगी। भाजपा जो कहती है, वह करके भी दिखाती है। श्री साव ने प्रदेश महामंत्री त्रय ओ.पी. चौधरी, विजय शर्मा और केदार कश्यप सहित भाजपा नेताओं के साथ शुक्रवार को सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ के बैनरतले तूता में आंदोलित कर्मचारियों से आंदोलन स्थल पर पहुंचकर अपना पूरा समर्थन दिया और उन्हें विश्वास दिलाया कि भाजपा की सरकार बनते ही कर्मचारियों की न्यायसंगत मांगें पूरी की जाएंगीं।

इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री साव ने कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि धूप, गर्मी, ऊमस और बारिश के बावजूद अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे कर्मचारियों के हजारों परिवार की चिंता करने के बजाय प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक खानदान, एक परिवार की सेवा-चाकरी और चिंता कर रहे हैं।

श्री साव ने कहा कि कांग्रेस ने अपने पिछले चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया था कि सत्ता में आते ही 10 दिन में संविदा कर्मियों का नियमितीकरण किया जाएगा, लेकिन सरकार वादा पूरा करने में टाल-मटोल करती रही, बहानेबाजी करती रही। प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों के साथ वादाखिलाफी करके हजारों कर्मचारियों को आंदोलन के लिए बाध्य किया है। प्रदेश सरकार ने हर वर्ग के साथ-साथ कर्मचारियों को भी बार-बार धोखा दिया है। श्री साव ने कहा कि कर्मचारियों के साथ ही पूरे प्रदेश ने अब वादाखिलाफी करने वाली सरकार को सबक सिखाने का निश्चय कर लिया है। श्री साव ने आश्वस्त किया कि लाखो कर्मचारियों का दुःख-दर्द भाजपा परिवार का दुःख-दर्द है। प्रदेश के मुख्यमंत्री को छत्तीसगढ़ की तीन करोड़ जनता की कोई फिक्र नहीं है। अब इस प्रदेश सरकार का हिसाब नवम्बर में चुकता करने का मौका कर्मचारियों को मिल रहा है। ऐसी तानाशाह सरकार को उखाड़ फेंकें और आज से लाखो कर्मचारी अपने भविष्य की चिंता छोड़ दे, उनकी चिंता अब भाजपा करेगी। श्री साव ने कहा कि कर्मचारियों के संघर्ष में भाजपा हर कदम पर कर्मचारियों के साथ खड़ी है।

इससे पूर्व कर्मचारियों को प्रदेश उपाध्यक्ष, भूपेंद्र सवन्नी,प्रदेश महामंत्री केदार कश्यप, विजय शर्मा, ओपी चौधरी ने भी संबोधित किया और कर्मचारियों के प्रति संवेदनहीनता का परिचय देने के लिए प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। इस मौके पर भाजपा के प्रदेश मंत्री रामू रोहरा ,अनुसूचित जाति मोर्चा अध्यक्ष विकास मरकाम, , अमरजीत छाबड़ा आदि भी उपस्थित थे।

कांग्रेस के चेहरे पर कोयले की कालिखः बृजमोहन

रायपुर। भाजपा के वरिष्ठ नेता तथा छत्तीसगढ़ शासन के पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कोयला घोटाले के संदर्भ में कहा कि कांग्रेस का हाथ भ्रष्टाचार के साथ है। कोयले की कालिख में छत्तीसगढ़ कांग्रेस भी पुती हुई है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की सीबीआई विशेष अदालत ने छत्तीसगढ़ के एक पुराने कोल ब्लॉक आवंटन के मामले में कांग्रेस के पूर्व सांसद , उनके पुत्र सहित अन्य को दोषी ठहराया है। यह छत्तीसगढ़ के फतेहपुर ईस्ट कोल ब्लॉक से संबंधित है। इस मामले में आपराधिक धोखाधड़ी कर कोल ब्लॉक हासिल किया गया था। उन्होंने कहा कोयले की कालिख में कांग्रेस का चेहरा हमेशा काला हुआ है। एक लाख 76 हजार करोड़ के कोयला घोटाले को भारतीय जनता पार्टी ने सामने लाया। इसके बाद मोदी जी ने सारे कोल ब्लॉक कैंसिल करके नीलामी के आधार पर कोल ब्लॉक आवंटन की व्यवस्था की। छत्तीसगढ़ में कोयले की कालिख में पूरी सरकार का चेहरा रंगा हुआ है। कांग्रेस और भ्रष्टाचार एक दूसरे के पूरक हैं। छत्तीसगढ़ के कॉल ब्लॉक के मामले में सीबीआई अदालत ने धोखाधड़ी के माध्यम से कोल ब्लॉक प्राप्त करने का मामला प्रमाणित पाया है। कांग्रेस की सरकार ने तो इस मामले को समाप्त कर दिया था परंतु अदालत ने कहा कि हम इस मामले को समाप्त करने की अनुमति नहीं देते हैं और जांच के आधार पर यह साबित हुआ है कि कांग्रेस के दिल्ली के नेताओं से लेकर, कांग्रेस के शीर्षस्थ नेताओं से लेकर राज्यों के नेता भी कोल घोटाले में बड़े माध्यम रहे हैं। कोल घोटाले में जिनको प्रमुख रूप से दोषी पाया गया है वह कांग्रेस के पूर्व सांसद हैं, उनके बेटे हैं, उद्योगपति हैं, उस समय के सचिव हैं। इस बारे में सोनिया जी को, राहुल जी को स्पष्ट करना चाहिए कि छत्तीसगढ़ के घोटालेबाज लोगों के खिलाफ क्या कांग्रेस कार्रवाई करेगी? छत्तीसगढ़ में 500 करोड़ का घोटाला होने का आरोप है। हम कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी कोयले की कालिख से पुती हुई है और कोयले की कालिख से ही अपनी पार्टी को चलाती है और ऐसी पार्टी को आने वाले समय में 2023 में और 2024 में जनता खारिज करेगी।

बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि जैसे बरसात के समय लोग अपने घरों की मरम्मत करते हैं, वैसे ही कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में मरम्मत का काम किया है और कहीं ऐसा न हो पूरी कांग्रेस पार्टी बारिश में बह जाएं। क्योंकि दिल्ली से लेकर छत्तीसगढ़ तक कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। डीएमएफ घोटाले के आरोप लगाने वाले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को अपमानित करके प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया गया ।

बाल सुधार गृह में नशीले पदार्थ कर्मचारियों पर मामला दर्ज

रायपुर। राजधानी रायपुर के माना स्थित बाल संप्रेक्षण गृह के नशीले पदार्थ सप्लाई करने के मामले में पुलिस ने तीन कर्मचारियों पर मामला दर्ज किया है। आरोप है कि, ये कर्मचारी ड्यूटी के दौरान बच्चों को नशे का सामान सप्लाई करते थे। फ्लिहाल पुलिस इस पुरे मामले की जांच में जुट गयी है।

राजधानी रायपुर के बाल संप्रेक्षण गृह में अव्यवस्था पर पहले से ही सवाल उठते रहे है किंतु इस बार एक विडियो ने बाल संप्रेक्षण गृह की पोल खोल दी है। दरअसल बाल संप्रेक्षण गृह का एक विडियो वायरल हुआ जिसमें तीन लड़के दिखाई दे रहे हैं। ये वीडियो में कह रहे हैं कि, जेल में हैं हम और जेल में राज करते हैं। समझ लेना, तिल्दा वाले को बता देना,जेल में तुम्हारा बाप बैठा है। बता देना, अपन जल्द वापस आएगा। ये देखो लाइटर, मोबाइल और नशा । इसके साथ लड़के 500 के नोट भी दिखा रहे हैं। बताया जाता है कि ये लड़के एक यहां एक हत्याकांड के आरोप में बंद हैं।

मालवीय रोड में खुदाई कार्य जारी होने से आवाजाही हो रही प्रभावित

रायपुर। नगर निगम रायपुर एवं लोकनिर्माण विभाग द्वारा संयुक्त रूप से इन दिनों जयस्तंभ चौक मालवीय रोड से कोतवाली चौक तक केबल अंडर ग्राउंड करने के लिए लंबे गढ्डे खोदे गये हैं। केबल डालने का कार्य मालवीय रोड के व्यापारियों के अनुसार अत्यंत धीमी गति से किया जा रहा है जिसके चलते सुबह से रात तक लंबा जाम लगने की वजह से आवाजाही प्रभावित हो रही है। गोलबाजार न केवल राजधानी अपितु आसपास के जिलों के व्यापारियों की खरीदी हेतु आने का मुख्य केंद्र है। शहर के प्रमुख मार्गों में खोदे गये गढ्डों के चलते आए दिन चोटिल हो रहा है वहीं घड़ी चौक से कालीमाई मंदिर के बीच केंदीय आयकर विभाग के सामने खोदा गया बड़ा गढ्डा आए दिन दुर्घटनाओं के कारण जानलेवा सिद्ध हो रहा है शहर के प्रबुद्ध नागरिक सुधीर शर्मा प्रभात सोनी एवं अमिताभ शर्मा ने लोकनिर्माण मंत्री एवं नगरीय प्रशासन मंत्री से शहर के मुख्य मार्गों पर लग रहे यातायात जाम के मद्देनजर जल्द से जल्द सड़कों का डामरीकरण कराने की मांग किये हैं।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.